मुंबई(महाराष्ट्र) से प्रकाशित

हिन्दी दैनिक

उत्तरशक्ति

मुंबई
वर्षः 8 अंक 131
शनिवार, 22 नवम्बर 2025
मूल्य 3 रुपए, पृष्ठ-6
RNI NO. MAHHIN/2018/76092
email ID- uttarshaktinews@gmail.com
www.uttarshaktinews.com

हर खबर निष्पक्षता के साथ

चार नए श्रम संहिताएँ सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेंगे: पीएम मोदी

नई दिल्ली, 21 नवम्बर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जोर देकर कहा कि आज से लागू होने वाले चार नए श्रम संहिताएँ सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेंगे और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता, 2020 आज से लागू होने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने पर पोस्ट किया कि श्रमेव जयते! आज हमारी सरकार ने चार श्रम संहिताओं को लागू कर दिया है। यह आजादी के बाद से सबसे व्यापक और प्रगतिशील श्रम-उन्मुख सुधारों में से एक है। यह हमारे श्रमिकों को काफी सशक्त बनाता है। यह अनुपालन को काफी सरल बनाता है और 'व्यापार करने में आसानी' को बढ़ावा देता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि इन चार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन से न्यूनतम और समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित होगा, साथ ही सुरक्षित कार्यस्थल और लाभकारी अवसर, विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के लिए, सुनिश्चित होंगे।

उन्होंने कहा कि ये संहिताएँ सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम और समय पर वेतन भुगतान, सुरक्षित कार्यस्थल और हमारे लोगों, विशेष रूप से नारी शक्ति और युवा शक्ति के लिए लाभकारी अवसरों के लिए एक मजबूत आधार के रूप में काम करेंगी।

उन्होंने आगे कहा कि ये सुधार रोजगार सृजन को बढ़ावा देंगे, उत्पादकता बढ़ाएँगे और भारत को विकसित होने की ओर अग्रसर करेंगे। यह एक भविष्य के लिए तैयार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगा जो श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा और भारत के आर्थिक विकास को मजबूत करेगा। ये सुधार रोजगार सृजन को बढ़ावा देंगे, उत्पादकता बढ़ाएँगे और विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा को गति देंगे।

एक ऐतिहासिक निर्णय में, भारत सरकार ने घोषणा की है कि चार श्रम संहिताएँ - वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता, 2020 - 21 नवंबर से प्रभावी हो रही हैं, जिससे 29 मौजूदा श्रम कानूनों को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है। श्रम विनियमों का आधुनिकीकरण, श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देना और श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को कार्य की बदलती दुनिया के साथ सरेखित करके, यह ऐतिहासिक कदम भविष्य के लिए तैयार कार्यबल और मजबूत, लचीले उद्योगों की नींव रखता है जो आत्मनिर्भर भारत के लिए श्रम सुधारों को आगे बढ़ाएंगे।

निर्वाचन आयोग ने कोलकाता के सात बीएलओ को कारण बताओ नोटिस भेजा

कोलकाता, 21 नवम्बर। निर्वाचन आयोग ने कोलकाता के बेलियाघाटा निर्वाचन क्षेत्र के सात बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) गणना फॉर्म के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में खामियों का हवाला देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

एक अधिकारी ने बताया कि शिकायत एकत्रित गणना प्रपत्रों के अनुचित एवं अपूर्ण डिजिटलीकरण से संबंधित है। उन्होंने कहा, बीएलओ को शुक्रवार दोपहर तक यह बताने का निर्देश दिया गया है कि वे सौंपे गए कार्यों को ठीक से पूरा करने में क्यों विफल रहे।

उन्होंने कहा कि यदि स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दूसरे चरण का संचालन कर रहा है, जहां अगले साल की शुरूआत में चुनाव होने हैं।

यह प्रक्रिया चार नवंबर को शुरू हुई और चार दिसंबर तक जारी रहेगी। मतदाता सूची का मसौदा नौ दिसंबर को जारी किया जाएगा और अंतिम मतदाता सूची सात फरवरी को प्रकाशित की जाएगी।

हरियाणा पंचकूला को मॉडल सिटी में बदलेगा: सैनी

हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि पंचकूला को आधुनिक, सुव्यवस्थित और आदर्श शहर के रूप में विकसित करना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है, ताकि यह शहरी उत्कृष्टता का मानक बन सके। मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार शाम को पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमडीए) की एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए लोगों के लिए नागरिक बुनियादी ढांचे को उन्नत करने, स्वच्छता मानकों में सुधार लाने और समग्र शहरी पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए एक एकीकृत और तेज गति वाले दृष्टिकोण का आह्वान किया।

सैनी ने सभी शहर की सड़कों को उत्कृष्ट स्थिति में बनाए रखने की जरूरत बताई और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां भी सड़कें क्षतिग्रस्त या जर्जर हों, उन्हें तुरंत ठीक किया जाए। उन्होंने कहा कि पंचकूला में उच्च गुणवत्ता वाला, सुरक्षित और सुगम सड़क तंत्र विकसित होना चाहिए।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने फुटपाथों की समय पर मरम्मत और रखरखाव सुनिश्चित करने के साथ-साथ शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए समग्र सड़क गुणवत्ता सुधारने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने आवारा पशुओं से जुड़े मुद्दों को भी शीघ्र सुलझाने के आदेश दिए। बैठक के दौरान पीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के एम पांडुरंग ने बताया कि सेक्टर 32, पंचकूला में आधुनिक शूटिंग रेंज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए 173.48 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी जा चुकी है और आगे की औपचारिकताएं जल्द पूरी होंगी।

दिल्ली में 48 घंटे की कार्रवाई में 800 से अधिक साइबर अपराध के आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने साई-हॉक नामक 48 घंटे के अभियान में विभिन्न साइबर अपराध मॉड्यूल से जुड़े 800 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है या उन्हें कानूनी नियंत्रण के तहत रखा है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

संयुक्त पुलिस आयुक्त (इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस) रजनीश गुप्ता ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि शुक्रवार की सुबह नौ बजे तक 48 घंटे के अभियान में पुलिस ने कुल 877 लोगों को गिरफ्तार किया या उन्हें कानूनी नियंत्रण में रखा है, जबकि साइबर अपराधों के सिलसिले में 509 व्यक्तियों को नोटिस भेजे गए हैं। नौकरी, निवेश, और वर्क-फ्रॉम-होम जैसे धोखाधड़ी के मामलों का भंडाफोड़ किया गया है, जबकि लोगों को ठगने में शामिल कई कॉल सेंटर पर भी छापा मारा गया है। और विवरण की प्रतीक्षा है।

अंबरनाथ में सड़क हादसे में 4 लोगो की मौत, घायलों का इलाज जारी

अंबरनाथ। अंबरनाथ पश्चिम मटका चौक से पूर्व को जोड़ने वाले रेलवे ब्रिज पर हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में चार पहिया वाहन सहित कई दो पहिया वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। घटना स्थल पर अंबरनाथ पुलिस पहुंचकर घटना की जानकारी जुटाने में लगी है। सड़क हादसा इतना भयंकर था कि मरने मरने वालों की शिनाख्त करने में पुलिस को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।सूत्रों की माने तो इस मामले में 2 लोग गम्भीर जख्मी बताए जा रहे है। मिली जानकारी के अनुसार अंबरनाथ पूर्व पश्चिम को जोड़ने वाला रेलवे ब्रिज पर 7 बजे के दरम्यान चार पहिया एक बड़ा हादसा हुवा जिसमे 4 लोगो की मौत और 2 लोग जख्मी होने की खबर है। यह हादसा इतना भयंकर था कि रेलवे ब्रिज से कार चालक नीचे गिर गया। इस मामले में मृतकों के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। घटना स्थल पर अंबरनाथ पुलिस पहुंचकर घायलों को उल्हासनगर के सेंट्रल अस्पताल में भर्ती किया गया । मृतकों के विषय में पुलिस अधिक जानकारी जुटाने में लगी है। समाचार लिखे जाने तक मामले की पुष्टि आधिकारिक तौर पर नही हो सकी है।

स्मार्ट मीटर के दबाव व निजीकरण के खिलाफ भड़के बिजलीकर्मी

- सिगरा स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर जमकर नारेबाजी, 27 नवंबर को प्रदेशभर में उग्र प्रदर्शन

सुरेश गांधी

वाराणसी। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के बैनर तले शुक्रवार को आंदोलन के 359वें दिन बनारस के बिजलीकर्मियों ने बिजली निजीकरण, कारपोरेशन आदेशों के विरुद्ध संविदाकर्मियों की अनैतिक छंटनी और समझौते के उल्लंघन पर विभागीय अधिकारियों द्वारा घरों पर स्मार्ट मीटर लगाने के दबाव के खिलाफ सिगरा स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए चेताया कि संघर्ष समिति के साथ हुए समझौतों को तोड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिजलीकर्मियों ने स्पष्ट संदेश दिया, जब तक निजीकरण वापस नहीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

वक्ताओं ने कहा कि 25 जनवरी 2000 को संघर्ष समिति और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच हुए समझौते में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि अंतरण योजना से पहले की सभी कल्याणकारी योजनाएँ पूर्ववत जारी रहेंगी। इसके बावजूद अधिकारियों द्वारा बिजलीकर्मियों के घरों पर स्मार्ट मीटर लगाने का दबाव बनाया जा रहा है। कर्मचारियों ने बताया कि साल 2005 में विद्युत नियामक आयोग बनने के बाद ऊर्जा प्रबंधन द्वारा एलएमवी-10 कैटेगरी समाप्त कर दी गई, जिससे कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधा बंद हो गई। अब ऊर्जा प्रबंधन ह्यएनर्जी अकाउंटिंगह्ल की बात कर रहा है, जबकि वर्ष 2000, 2020, 2022 और 2023 में हुए लिखित समझौतों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। इसी कारण कर्मचारियों का ऊर्जा प्रबंधन से विश्वास उठ गया है।

संघर्ष समिति ने बताया कि आदेश संख्या, 295 के अनुसार नगरीय वितरण मंडल-द्वितीय में 677 कुशल व अकुशल श्रमिकों की जरूरत है, लेकिन वर्तमान टेंडर में केवल 489 कर्मियों को रखने की व्यवस्था है।

इससे डेढ़ सौ संविदा कर्मियों पर छंटनी की तलवार लटक गई है, जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। संघर्ष समिति ने अधीक्षण अभियंता को एक सप्ताह का समय दिया है कि वे संविदा कर्मियों की संख्या पुनः बढ़ाएँ। चेतावनी दी गई कि यदि एक भी कर्मचारी हटाया गया तो पूरे मंडल के बिजलीकर्मी संघर्ष समिति के नेतृत्व में कठोर आंदोलन करेंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों की होगी।वक्ताओं ने साफ कहा कि संघर्ष समिति से हुए समझौते का उल्लंघन कर यदि किसी बिजली कर्मचारी के घर स्मार्ट मीटर लगाने की कोशिश की गई, तो संबंधित टीम को कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। संविदा कर्मियों और कैश काउंटर ऑपरेटरों को हटाने की किसी भी कार्रवाई पर संघर्ष समिति प्रदेशव्यापी आंदोलन के लिए बाध्य होगी।संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि पूर्वांचल व दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण के विरोध में पिछले एक साल से चल रहा आंदोलन अब राष्ट्रव्यापी समर्थन प्राप्त कर चुका है। देशभर के बिजलीकर्मी कई बार उत्तर प्रदेश के आंदोलन के समर्थन में एकजुट हुए हैं. उन्होंने घोषणा की कि 27 नवंबर को पूरे उत्तर प्रदेश में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बिजलीकर्मियों, संविदाकर्मियों, जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओं ने संकल्प दोहराया कि निजीकरण वापस लेने और आंदोलन के दौरान की गई सभी उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों को रद्द करने तक संघर्ष जारी रहेगा।

हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: अल-फलाह प्रमुख के घर पर तोड़फोड़ पर लगी रोक

भोपाल, 21 नवम्बर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अल-फलाह विश्वविद्यालय के अध्यक्ष जवाद सिद्दीकी से जुड़े महू स्थित आवास पर चल रही तोड़फोड़ की कार्यवाही पर तत्काल रोक लगाते हुए 15 दिनों की अंतरिम रोक लगा दी, जिससे महू छावनी बोर्ड की सभी कार्रवाई प्रभावी रूप से स्थगित हो गई। यह आदेश अब्दुल मजीद द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जो अपने परिवार के साथ उस घर में रहते हैं। न्यायालय ने निर्देश दिया कि अगले 15 दिनों तक कोई तोड़फोड़ या संरचनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिसके बाद मामले पर फिर से सुनवाई की जाएगी। मजीद ने कई आधारों पर विध्वंस नोटिस को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि बोर्ड ने यह नहीं बताया कि संरचना का कौन सा हिस्सा कथित रूप से अनधिकृत निर्माण के अंतर्गत आता है। उन्होंने कहा कि नोटिस में वर्तमान स्थलीय स्थिति के बजाय 1996-97 के दस्तावेजों का हवाला दिया गया है, जिससे कार्रवाई का आधार स्पष्ट नहीं है।

मजीद ने यह भी बताया कि नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के 2025 के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया है, जो विध्वंस से संबंधित कार्यवाही के लिए अनिवार्य है, उन्होंने कहा कि इस चूक के कारण बोर्ड का कदम अस्वीकार्य है। स्वामित्व स्पष्ट करने के लिए, याचिका में बताया गया कि यह घर मूल रूप से सिद्दीकी के पिता हम्माद सिद्दीकी का था, जिन्होंने बाद में इसे अपने बेटे को उपहार में दे दिया। बाद में जावद सिद्दीकी ने यह संपत्ति अब्दुल मजीद को दान कर दी, जो वर्षों से वहाँ रह रहे हैं। इसके बावजूद, छावनी बोर्ड ने तीन दिन की अंतिम चेतावनी के साथ ध्वस्तीकरण नोटिस जारी कर दिया। याचिका के मुख्य बिंदुओं, नोटिस में स्पष्टता की कमी, दशकों पुरानी कार्यवाही पर निर्भरता और सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का पालन न करने को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने अस्थायी राहत प्रदान की और बोर्ड की कार्रवाई पर रोक लगा दी।अगली सुनवाई 15 दिनों के बाद होने की उम्मीद है, जब अदालत तय करेगी कि मामले की आगे की कार्यवाही कैसे आगे बढ़ेगी।

भ्रष्टाचार और जंगलराज से समझौता बना कांग्रेस की हार का कारण

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) की विशेष अदालत ने पिछले महीने आई.आर.सी.टी.सी. होटल घोटाला मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। सी.बी.आई. के अनुसार, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव के अलावा राज्यसभा सदस्य प्रेमचंद गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता, आई.आर.सी.टी.सी. अधिकारियों, कोचर ब्रदर्स समेत कुल 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए थे। यह खबर पूरे देश में पढ़ी-सुनी गई। यदि किसी ने नहीं देखी तो वह है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस ने लालू यादव के भ्रष्टाचार और जंगलराज के अन्य मामलों की तरह इसे भी नजर अंदाज कर दिया। कांग्रेस यह भूल गई कि यदि ऐसे मामलों की अनदेखी की गई तो मतदाता भी उसे भूल जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में यही हुआ। मतदाता भूल गए कि कांग्रेस भी एक राष्ट्रीय और प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दल है। कांग्रेस ने सत्ता के लिए भ्रष्टाचार से समझौता किया। मतदाताओं ने कांग्रेस के इस रवैये को मतों से ठुकरा दिया। सर्वाधिक आश्चर्य की बात यह है कि कांग्रेस ने पिछली गलतियों से जरा भी सबक नहीं सीखा। भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था आज भी देश में प्रमुख मुद्दा है। विकास और दूसरे मुद्दे इसकी नींव पर खड़े होते हैं यदि नींव ही कमजोर होगी तो विकास की इबारत नहीं लिख पाएगी। कांग्रेस ने बिहार में लालू यादव की पार्टी से सत्ता के लिए समझौता कर अपने पैरों पर फिर से कुल्हाड़ी मारने का काम किया है।

कांग्रेस को बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में से मात्र 6 सीटें मिलीं। इस शर्मनाक हार की जिम्मेदार खुद कांग्रेस है। कांग्रेस अब इस जिम्मेदारी से भागने के लिए फिर से वही पुराना वोट चोरी, सरकारी मशीनरी के चुनाव में दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। अभी भी कांग्रेस इस सच्चाई का सामना करने को तैयार नहीं है कि उसने एक महाभ्रष्ट लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से सीटों का समझौता करके भारी भूल की है। बिहार के मतदाताओं ने इन दोनों दलों को तगड़ा सबक सिखाया है। कांग्रेस ने आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबे लालू परिवार के जरिए चुनावी वैतरणी पार करने का गलत निर्णय लिया। यह जानते हुए भी कि मतदाता इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपराधी परिवार के साथ चुनावी तालमेल की कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ गई। भाजपा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार और जंगलराज को प्रमुख मुद्दा बनाया। कांग्रेस इसके बचाव में कोई दलील देकर मतदाताओं को संतुष्ट नहीं कर सकी। बिहार में चुनाव हो और चारा घोटाले से जुड़ी कहानियां सामने न आएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये घोटाला ही ऐसा था कि 30 साल बाद भी लोग इसके बारे में बात करते हैं और जानने की चाहत रखते हैं। कांग्रेस ने 950 करोड़ रुपए के घोटाले में अपने प्रमुख सहयोगी और राजद प्रमुख लालू प्रसाद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए पर्दे के पीछे से राजनीतिक चालें चलीं लेकिन वे असफल रहीं। वर्ष 1990-96 के दौरान सामने आया चारा घोटाला बिहार पशुपालन विभाग में हुआ। यह घोटाला मुख्य रूप से 1990 के दशक में हुआ। इस समय लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। भ्रष्टाचार के ऐसे ढेरों मामलों के अलावा कांग्रेस लालू यादव के शासन के दौरान जंगल राज को भूल गई। लालू राज के दौरान अपराध की घटनाओं में वृद्धि हुई। अपहरण (किडनैपिंग) की वारदातें बढ़ीं। सड़क पर बढ़ती असुरक्षा भी इसमें शामिल थी। गुंडागर्दी और बाहुबल का प्रभाव था। कई जगह दबंगों और बाहुबली नेताओं का वर्चस्व था। प्रशासन पर राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप लगे थे। अर्थव्यवस्था और विकास में गिरावट आंकी गई थी। उद्योग, शिक्षा और बुनियादी ढांचे की स्थिति कमजोर हुई थी। बिहार को देश के ह्यसबसे पिछड़े राज्योंह्व में गिना जाने लगा था। वर्ष 1992 से 2004 तक, अपहरण के कुल 32,085 मामले दर्ज किए गए थे। ऐसे कितने मामले दर्ज नहीं किए गए। बिहार पुलिस की वैबसाइट के अनुसार, 2001-2005 के बीच हत्याओं की संख्या 20,000 के करीब है। 90 के दशक में स्थिति का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। बिहार में दूसरा जंगलराज चुनावों में होने वाली हिंसा, बूथ कैप्चरिंग और धांधली से जुड़ा था, जिसका अंत भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन.शेषन ने अपने कड़े चुनाव सुधारों से किया था। टी.एन.शेषन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त 1990-1996 तक थे, तब उन्होंने इस सिस्टम को बदलने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए थे। बिहार में इन सुधारों का प्रभाव सबसे ज्यादा दिखा। इस दूसरे वाले जंगलराज में बदमाशों या राजनीतिक कार्यकत्र्ताओं द्वारा पूरे बूथ पर कब्जा करना, वोटिंग मशीन-बैलेट पेटी उठा ले जाना या खुद वोट डाल देना, वोटरों को धमकाना या बूथ से भगा देना जैसी चीजें शामिल थीं। कांग्रेस यदि गंभीर होती तो अपने शासित राज्यों में किसी एक का उदाहरण देकर मतदाताओं को विश्वास दिला सकती थी कि वह भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरैंस की नीति पर अमल करती है। कांग्रेस को यह समझना होगा कि राजद जैसे दागदार क्षेत्रीय दलों की तुलना वह एक प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी है। सिर्फ एक राज्य में सत्ता के लिए भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से समझौता करने की भारी कीमत पूरे देश में चुकानी पड़ सकती है। यही कीमत दूसरे राज्यों के अलावा अब कांग्रेस ने बिहार में चुकाई है।-योगेन्द्र योगी

आतंकवाद की ओर जा रहे हैं कुछ डाक्टर

मैडिसिन के डाक्टर हमेशा से हमारे कामों की लिस्ट में सबसे ऊपर रहे हैं, जिनकी इस दुनिया में हर इंसान तारीफ करता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे अपनी जिंदगी में कभी न कभी डाक्टर की जरूरत न पड़ी हो। डाक्टरों को नेक इंसान माना जाता है जो दूसरे इंसानों को जिंदा और ठीक रखने की फिक्र करते हैं। 10 नवंबर,2025 को दिल्ली में लाल किले के पास मैट्रो स्टेशन के बाहर हुए धमाके में 13 आदमी मारे गए और कई आदमी और औरतें घायल हो गई, यह न सिर्फ हमारी मजबूत सरकार के लिए बल्कि हमारे देश के आम लोगों के लिए भी एक बड़ा झटका था। पाकिस्तान में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक टैरर मॉड्यूल का पता चला। गिरफ्तार किए गए ज्यादातर लोग डाक्टर हैं। इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? आम आदमी ऐसे टैरर मॉड्यूल की कल्पना भी नहीं कर सकता जिसमें एक डाक्टर भी शामिल हो। अब उसे बताया जा रहा है कि इस खास मॉड्यूल में ज्यादातर डाक्टर हैं जो सभी इस्लाम को मानते हैं लेकिन जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और बंगाल जैसे अलग-अलग राज्यों से हैं। सिर्फ सबसे होशियार स्टूडैंट ही मैडिकल कॉलेज में सीट पक्की कर सकते हैं। पढ़ाई साढ़े 5 साल की होती है और अगर स्टूडैंट मैडिसिन की किसी भी ब्रांच में स्पैशलाइज करना चाहता है तो उसे 2 साल या उससे ज्यादा और लगेंगे, जिसके बाद जरूरी स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करनी होगी। जिन डॉक्टरों ने अपनी जवानी के सबसे अच्छे साल ऐसी जिंदगी की तैयारी में बिताए हैं जो दूसरों को जिंदा रहने में मदद करती है, वे अपना मकसद क्यों छोड़कर सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों को मैसेज देने के लिए बेगुनाह लोगों को मारने और घायल करने पर उतर आएं? इसका जवाब पिछले कुछ सालों में खोजे गए दूसरे टैररिस्ट मॉड्यूल में मिल सकता है। अभिनव भारत एक अकेला मॉड्यूल था जो हैरानी की बात है कि ज्यादातर कम्युनिटी में घुसा हुआ था, जिसे महाराष्ट्र के एंटी-टैररिस्ट स्क्वॉड ने खोजा था। पॉलिटिकल फील्ड में फायदेमंद पोजीशन वाले लोगों में भी जो गहरा गुस्सा था, उसे हमें अपने मन की आंखों में, उन लोगों तक पहुंचाना होगा जो इस समीकरण के शिकार थे। जब भारत के इकलौते मुस्लिम-बहुल राज्य को राज्य का दर्जा नहीं दिया गया और उन लोगों ने उसे कमतर दर्जा दिया, जिन्हें उसका सैक्युलर और बराबरी के रैंक में स्वागत करना चाहिए था, उसे बुरी तरह याद दिलाया गया कि उस पर कभी भरोसा नहीं किया जाएगा तो दुश्मनी और नफरत को पनपने के लिए जमीन तैयार हो गई। मोदी-शाह की जोड़ी का मजबूत गवर्नेंस मॉड्यूल जम्मू-कश्मीर में अपने तख्तापलट की शेखी बघारता रहा। राज्य में और ज्यादा सैनिक और पैरा-मिलिट्री भेजी गई, इस उम्मीद में कि बॉर्डर पार से आतंकवाद और कश्मीरियों के बीच अलगाववादी तत्व बेअसर हो जाएंगे। शुरू में ऐसा सरप्राइज फैक्टर की वजह से हुआ। राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी ने इस मुश्किल और हमेशा रहने वाली हिंदू-मुस्लिम समस्या को बहुत सोच-समझकर और बारीकी से सुलझाया था। उन्होंने पूर्व रॉ चीफ ए.एस. दुलत पर भरोसा किया, जिन्होंने फारूख अब्दुल्ला के साथ पक्की दोस्ती की थी। अब्दुल्ला परिवार ही काफी हद तक कश्मीरी मुसलमानों के भारत के साथ अपने मुस्लिम-बहुल पड़ोसी पाकिस्तान के साथ इलाके के झगड़े में साथ देने के लिए जिम्मेदार रहा है। लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार कुछ और ही सोचती थी। उसने कश्मीरी मुसलमानों को दबाने के लिए आक्रामकता का इस्तेमाल करने का फैसला किया और अपने ही वोटरों को यह साबित करने का फैसला किया कि वह कांग्रेस और यहां तक कि वाजपेयी की भाजपा सरकार के उलट एक मजबूत और ताकतवर सरकार है। ऐसा तरीका शायद ही कभी काम करता है। अगर वहां के लोग भाईचारे की उम्मीद को पसंद नहीं करते हैं तो भारतीय सरकार या कोई भी राज्य हथियारों के बल पर राज नहीं कर सकता। ऐसी जगहों पर आतंकवाद पनपता है।

वैश्विक व्यापार में रुपये की नई दस्तक

-प्रियंका सौरभ

भारत आज उभरती वैश्विक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है और इसी आकांक्षा के साथ वह अपनी मुद्रा–भारतीय रुपये–को अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में अधिक स्वीकार्य बनाने की दिशा में गंभीर प्रयास कर रहा है। बदलते भू-राजनीतिक वातावरण, डॉलर-निर्भरता से जुड़ी अनिश्चितताओं तथा बहुध्रुवीय आर्थिक व्यवस्था के उभार ने यह अवसर प्रदान किया है कि भारत क्षेत्रीय और वैश्विक व्यापार में रुपये के उपयोग को बढ़ाए। इसी संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली की शुरुआत और इसे अनेक देशों के साथ लागू करने की कोशिश रुपये को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने वाली निर्णायक पहल बनकर उभरी है।

रुपये के प्रसार के पीछे कई प्रेरक कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण अमेरिकी डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना है, क्योंकि डॉलर आधारित भुगतान तंत्र अनेक बार राजनीतिक तनाव, प्रतिबंधों और वैश्विक वित्तीय अस्थिरता के समय जोखिम पैदा करता है। रूसझ्रयूक्रेन संघर्ष के बाद भारत ने अनुभव किया कि डॉलर आधारित तंत्र के कारण कई लेनदेन बाधित हो जाते हैं और व्यापार प्रभावित होता है। यदि व्यापार सीधे स्थानीय मुद्राओं में हो, तो भुगतान अधिक सुगम और सुरक्षित हो सकता है तथा विदेशी मुद्रा भंडार पर भी अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता। साथ ही, कई देश अब अपने व्यापार में स्थानीय मुद्राओं के प्रयोग की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे डॉलर-केंद्रित व्यवस्था धीरे-धीरे परिवर्तित हो रही है। भारत भी इस परिवर्तनशील प्रवृत्ति का स्वाभाविक हिस्सा है।

भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि और बढ़ते व्यापारिक संबंध भी रुपये-आधारित निपटान की आवश्यकता को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, भारतझ्ररूस व्यापार पिछले दो दशकों में कई गुना बढ़ा है, परन्तु इस व्यापार में रुपये का उपयोग सीमित है। मुद्रा-आधारित विकल्प बढ़ने से न केवल व्यापार गति पकड़ता है बल्कि भारतीय निर्यातकों को विनिमय दर के उतारझ्रचढ़ाव और हेजिंग लागत से भी राहत मिलती है। दीर्घकाल में वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य मुद्रा भारत की आर्थिक शक्ति और राजनीतिक प्रभाव का संकेत भी बनती है। भारत के 30 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था और 1 खरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य की दिशा में यह एक अनिवार्य कदम माना जा रहा है।

हालाँकि, रुपये के वैश्वीकरण के मार्ग में कई चुनौतियाँ भी हैं। अनेक देशों को अभी भी डॉलर या अपनी स्थानीय मुद्रा अधिक स्थिर विकल्प लगती है। कुछ देशों को रुपये की विनिमय दर की स्थिरता पर भरोसा कम है। व्यापारिक साझेदारों के साथ मूल्य-वृद्धि आधारित वस्तुओं का आदानप्रदान सीमित होने से भी रुपये के व्यापक प्रयोग की संभावना घटती है। भारतीय निर्यातकों में भी रुपये आधारित निपटान के प्रति जागरूकता कम है, जिसके कारण वे इस विकल्प का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। अंतरराष्ट्रीय भुगतान और संदेश प्रणाली की सीमित परस्पर संपर्कता भी रुपये की स्वीकार्यता को धीमा करती है, क्योंकि अभी भी बड़ी संख्या में देश पारंपरिक वैश्वीकरण संदेश तंत्र पर निर्भर हैं।

रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण भारत को आर्थिक स्वायत्तता, भुगतान सुरक्षा और रणनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। इससे डॉलर पर निर्भरता घटती है, भुगतान बाधाएँ कम होती हैं और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घटता है। निर्यातकों को विनिमय दर से जुड़े जोखिम कम होते हैं, जबकि व्यापारिक साझेदारों के लिए भी स्थानीय मुद्रा में निपटान अधिक सरल व स्थिर होता है। स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली, त्वरित भुगतान तंत्र की वैश्विक पहुँच, तथा रुपये आधारित ऋण व्यवस्था जैसे कदम भारत को वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में अधिक प्रभावशाली भूमिका की ओर अग्रसर करते हैं।

इन चुनौतियों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली रुपये को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की दिशा में बड़ा बदलाव लेकर आई है। इस प्रणाली के अंतर्गत भारत अब संयुक्त रूप से सहमत देशों के साथ सीधे रुपये में व्यापार कर सकता है। संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, मॉरीशस और मालदीव के साथ हुए समझौते इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इससे न केवल दोनों देशों के बीच व्यापार सुगम होगा बल्कि बैंकिंग लागत और भुगतान समय में भी कमी आएगी। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक ने पड़ोसी देशों के बैंक एवं नागरिकों को रुपये में ऋण देने की अनुमति देकर नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे देशों में रुपये के उपयोग को बढ़ावा दिया है।

भारत ने अपने त्वरित भुगतान तंत्र को कई देशों से जोड़कर एक नई वित्तीय संपर्क व्यवस्था विकसित की है। संयुक्त अरब अमीरात के साथ त्वरित भुगतान तंत्र का जुड़ना छोटे व्यापारियों, पर्यटकों और प्रवासी भारतीयों के लिए तत्काल भुगतान को सरल बनाता है, जिससे रुपये की उपयोगिता और स्वीकार्यता दोनों बढ़ती हैं। इसके साथ ही भारत अपनी वित्तीय संदेश प्रणाली को भी साझेदार देशों की प्रणालियों से जोड़ने की दिशा में कार्य कर रहा है, जिससे परंपरागत वैश्विक संदेश तंत्र पर निर्भरता कम होगी। यह व्यवस्था भुगतान प्रक्रिया को राजनीतिक तनावों से सुरक्षित रखेगी और रुपये की विश्वसनीयता बढ़ाएगी। समग्र रूप से रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक और आर्थिक आकांक्षा का आधार है। स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली, डिजिटल भुगतान संपर्क, द्विपक्षीय वित्तीय संवाद और निर्यातकों की जागरूकता–ये सभी घटक मिलकर रुपये को वैश्विक व्यापार में अधिक उपयोगी और स्वीकृत मुद्रा बना सकते हैं। चुनौतियाँ अवश्य हैं, परंतु बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भारत के पास अवसर भी विशाल है। यदि भारत अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ आपूर्ति श्रृंखला को गहरा करे, भुगतान तंत्र को सरल बनाए और रुपये की स्थिरता को मजबूत करे, तो आने वाले वर्षों में रुपये की वैश्विक भूमिका निश्चित रूप से विस्तार पाएगी।

विश्व हैपीनेस रिपोर्ट की सीमाएँ और भारत में सहानुभूति-ढाँचे की अनिवार्यता

– डॉ. सत्यवान सौरभ

विश्व हैपीनेस रिपोर्ट हर वर्ष किसी देश की सुख-संतुष्टि का आकलन प्रस्तुत करती है। किंतु भारत जैसे विशाल, विविध और सांस्कृतिक रूप से जटिल देश के लिए यह रिपोर्ट कई बार उस यथार्थ को उजागर नहीं कर पाती जो समाज के भीतर गहरे स्तर पर मौजूद है। भारत की रैंकिंग अक्सर सौ से ऊपर दिखाई देती है, जबकि इसी अवधि में भारत ने स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक सुरक्षा, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, संरचनात्मक सुधारों और गरीबी कमी जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ दर्ज की हैं। यह विरोधाभास एक नैसर्गिक प्रश्न खड़ा करता है–क्या किसी देश के ह्लसुखह्व को केवल सर्वेक्षण-आधारित दृष्टिकोण से समझा जा सकता है? और क्या यह मापन भारतीय जीवन-मूल्यों और सामाजिक वास्तविकताओं को पकड़ने में सक्षम है?

विश्व हैपीनेस रिपोर्ट का आधार मुख्यतः स्व-आकलन है। सर्वेक्षणकर्ता उत्तरदाताओं से पूछते हैं कि वे जीवन को दस-स्तरीय सीढ़ी में कहाँ रखते हैं। यह सीढ़ी-संबंधी मूल्यांकनह्व पश्चिमी मनोविज्ञान में प्रयुक्त उस विचार पर आधारित है जिसमें सुख को व्यक्तिगत प्राप्तियों और परिस्थितियों के आधार पर मापा जाता है। परन्तु भारतीय समाज में सुख की अवधारणा केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामुदायिक, आध्यात्मिक और पारिवारिक आयामों से भी गहराई से जुड़ी होती है। भारतीय संस्कृति में संतोष, कर्तव्य, परस्पर सहायता, संबंधों की स्थिरता और आध्यात्मिक संतुलन भी सुख का महत्वपूर्ण आधार माने जाते हैं। इसलिए जब एक भारतीय उत्तरदाता से पूछा जाता है कि वह दस में से अपने जीवन को कितने अंक देगा, तो उसके भीतर कई सांस्कृतिक कारक सक्रिय होते हैं–विनम्रता, शांत-स्वीकृति, परिस्थिति को भाग्य-नियति से जोड़कर देखने की प्रवृत्ति, या समाज में शिकायत दिखाने से बचना। इसके परिणामस्वरूप अनेक भारतीय अपने जीवन को कम अंक दे सकते हैं, भले ही वे वस्तुतः अनेक स्तरों पर बेहतर स्थिति में हों।

सर्वेक्षण का नमूना आकार भी भारत के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता। एक अरब से अधिक जनसंख्या वाले, शहरी और ग्रामीण विविधताओं से भरे देश के लिए मात्र लगभग एक हजार लोगों के उत्तर पर आधारित निष्कर्ष असंतुलित हो सकते हैं। भारतीय समाज क्षेत्रीय, भाषायी, आर्थिक तथा सामाजिक स्तरों पर अत्यंत विषम है; एक छोटे नमूने का उपयोग करके उस विविधता का प्रतिनिधित्व संभव नहीं। एक जिले के ग्रामीण किसान की जीवन-संतुष्टि की अवधारणा दिल्ली के शहरी पेशेवर व्यक्ति से भिन्न हो सकती है। फिर भी, दोनों को समान पैमाने पर रखकर किसी राष्ट्रीय ह्लसुख-अंकह्व की व्याख्या करना वैज्ञानिक रूप से सीमित प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में प्रयुक्त सुख की अवधारणा भी सांस्कृतिक पक्षपात से प्रभावित है। पश्चिमी ढाँचा सुख को भौतिक उपलब्धियों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रत्यक्ष संतुष्टि से जोड़ता है, जबकि भारतीय समाज में अनेक बार सुख का अर्थ कठिनाइयों के बीच संतुलन बनाए रखना, भावनात्मक सहारा, सामुदायिक सहयोग या आध्यात्मिक शांति से भी जुड़ा होता है। यह अंतर सर्वेक्षणकर्ता की भाषा, शैली, शब्दों और उत्तरदाता के मनोभाव को प्रभावित करता है। अक्सर यह देखा गया है कि भारत के ग्रामीण या अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में उत्तरदाता ह्लजीवन के अंकह्व को किसी ऐसे प्रश्न की तरह स्वीकार करते हैं जिसमें शिकायत या असंतोष दिखाना उचित नहीं लगता। इसी वजह से कई भारतीय वास्तविक अनुभव होने के बावजूद संतुष्टि को अपेक्षाकृत कम आंकते हैं, जिससे परिणाम और अधिक विकृत होते हैं।

इसके विपरीत, भारत ने बीते वर्षों में सामाजिक कल्याण में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। करोड़ों लोगों तक निःशुल्क खाद्यान्न पहुँचाना, सर्वजन स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाओं के माध्यम से आधारभूत सुरक्षा सुनिश्चित करना, ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों में विस्तार, शिक्षा तथा महिला-शिशु पोषण कार्यक्रमों में बढोत्तरी–ये सब समग्र जीवन-गुणवत्ता को बढ़ाने वाले उपाय रहे हैं। किन्तु अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टें इन संकेतकों को केवल सीमित रूप से जोड़ती हैं, क्योंकि उनका मूल केंद्र ह्लअनुभूत संतुष्टिह्व पर आधारित है, न कि ह्लवस्तुनिष्ठ कल्याणह्व पर। यही कारण है कि वस्तुनिष्ठ रूप से बेहतर होती सुविधाएँ भी रिपोर्ट में पर्याप्त रूप से उजागर नहीं हो पातीं। भारत में गरीबी में कमी और स्वास्थ्य-सेवाओं की पहुँच में वृद्धि ने जीवन को अधिक सुरक्षित और स्थिर बनाया है, परन्तु सुख-सर्वेक्षण इस सकारात्मक परिवर्तन को मापने में अक्षम रहते हैं।

विश्व हैपीनेस रिपोर्ट में भारत की निम्न रैंकिंग अक्सर वास्तविक कल्याण स्थिति से अधिक सांस्कृतिक तथा धारणा-आधारित पूर्वाग्रहों को दर्शाती है। सुख मापने की पद्धति में निहित सीमाओं को समझते हुए भारत को अपने सामाजिक, संवेदनात्मक और सामुदायिक ढाँचे में सहानुभूति-आधारित सुधारों को बढ़ाना चाहिए।

ऐसे में, प्रश्न यह उठता है कि भारत को अपने भीतर ऐसा क्या बदलना चाहिए जिससे समाज अधिक भावनात्मक रूप से सुरक्षित, सहानुभूतिपूर्ण और संतुलित बन सके। इसका उत्तर ह्लसहानुभूति संरचनाह्व–एक व्यापक सामाजिक ढाँचा है जिसमें राज्य, समाज, संस्थान और समुदाय मिलकर नागरिकों को भावनात्मक सुरक्षा, मानसिक सहारा, संवाद और सहायता प्रदान करें। इस ढाँचे का पहला स्तंभ मानसिक-स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार है। भारत में मानसिक-स्वास्थ्य को लेकर अभी भी कई भ्रम और कलंक मौजूद हैं। लोग सहायता लेने में संकोच करते हैं, और प्राथमिक चिकित्सा ढाँचे में मानसिक स्वास्थ्य की अनुपस्थिति समस्या को बढ़ाती है। यदि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रशिक्षित परामर्शदाता हों, दूरभाष-आधारित सेवाएँ व्यापक हों और विद्यालयों-कॉलेजों में मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध हो, तो समाज में भावनात्मक असुरक्षा घट सकती है।

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू समुदाय-आधारित सहयोग है। भारतीय संस्कृति में पड़ोस, परिवार और सामाजिक संबंधों की शक्ति अत्यधिक रही है, परन्तु शहरीकरण और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के कारण यह संरचना कमजोर हो रही है। यदि स्थानीय समुदायों में संवाद-चक्र, सहारा-समूह, वरिष्ठ नागरिक सहायता-केंद्र, महिलाओं के लिए सुरक्षित समुदाय-स्थल और युवाओं के लिए साझा सहयोग मंच विकसित किए जाएँ, तो सामाजिक एकांत कम हो सकता है। सहानुभूति तभी विकसित होती है जब लोग एक-दूसरे के जीवन में उपस्थिति का अनुभव करें। सहानुभूति संरचना का तीसरा स्तंभ कार्यस्थल है। कार्यस्थलों पर तनाव, प्रतिस्पर्धा, लक्ष्य-दबाव और असुरक्षा बढ़ रही है, जिसके चलते कर्मचारियों का मानसिक संतुलन प्रभावित होता है। यदि संस्थान संवेदनशील नीति अपनाएँ–कार्य अवधि में लचीलापन, परामर्श सेवाएँ, साथी-सहयोग कार्यक्रम, नेतृत्व प्रशिक्षण में सहानुभूति-आधारित व्यवहार–तो यह वातावरण को स्वस्थ बना सकता है। एक सहानुभूतिपूर्ण संस्थागत संस्कृति न केवल कर्मचारी के मनोबल को बढ़ाती है बल्कि उत्पादकता भी बढ़ाती है।

चौथा आयाम विद्यालयों में भावनात्मक शिक्षा का है। बच्चों में सहानुभूति, अहिंसक संवाद, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सहयोगात्मक गतिविधियों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। यदि बच्चे अपनी भावनाएँ समझना, व्यक्त करना और दूसरों की भावनाओं को पहचानना सीखें, तो समाज भविष्य में अधिक संवेदनशील बनेगा। शैक्षणिक ढाँचा केवल परीक्षा-आधारित न रहकर जीवन-आधारित होना चाहिए।

पाँचवाँ पक्ष तकनीकी सहारा है। यदि तकनीक का उपयोग मानसिक-स्वास्थ्य और भावनात्मक सहयोग के लिए किया जाए–जैसे परामर्श ऐप, संकट में सहायता, छात्रों और युवाओं के लिए डिजिटल संवाद केंद्र–तो यह सहानुभूति संरचना को व्यापक बना सकता है। तकनीक का जिम्मेदार उपयोग सामाजिक संवेदनशीलता को बढ़ावा दे सकता है, बशर्ते उसकी निगरानी और नैतिकता मजबूत हो।

अंततः, राज्य के प्रशासनिक ढाँचे में भी सहानुभूति की आवश्यकता है। जब सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, परिवहन, सुरक्षा और न्याय-प्रणाली में कार्यरत लोग नागरिकों के प्रति अधिक करुणामय व्यवहार अपनाएँ, तो नागरिक-राज्य संबंध और भी मजबूत होते हैं। जनता की समस्याओं को सुनना, सम्मान देना और समाधान में मानवीय दृष्टिकोण अपनाना किसी भी लोकतंत्र की मजबूती का आधार है।

इस प्रकार विश्व हैपीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग उसे केवल नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने के बजाय एक अवसर के रूप में समझा जाना चाहिए। यह अवसर भारतीय समाज को यह विचार करने का मार्ग देता है कि कैसे हम ह्लसुखह्व को केवल व्यक्तिगत संतुष्टि के रूप में नहीं, बल्कि सामूहिक भावनात्मक सुरक्षा, सामाजिक भरोसा, संवेदनशील संवाद और मानसिक-स्वास्थ्य संरचना के रूप में विकसित कर सकते हैं। रिपोर्ट की पद्धति में चाहे जितनी सीमाएँ हों, यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि समाज किस दिशा में जाए। भारत यदि अपनी पारंपरिक सामुदायिक शक्ति को आधुनिक सामाजिक-कल्याण ढाँचे के साथ जोड़ दे, तो सहानुभूति-आधारित विकास की एक नई धारा स्थापित हो सकती है, जो वास्तविक सुख को और अधिक सुदृढ़ बनाएगी।

ट्रिब्यूनल सुधार और राष्ट्रपति संदर्भ संबंधी फैसले संवैधानिक मयार्दा और न्यायिक संयम की मिसाल

भारत की संवैधानिक संरचना में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन सदैव एक संवेदनशील विषय रहा है। दो दिनों में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दो महत्वपूर्ण फैसलों ने इस संतुलन पर नई बहसों को जन्म दिया है। एक ओर न्यायालय ने न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रमुख प्रावधानों को असंवैधानिक ठहराकर संसद और केंद्र सरकार को कठोर संदेश दिया है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत भेजे गए संदर्भ पर अपनी राय देते हुए न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि न तो राष्ट्रपति और न ही राज्यपाल पर अदालत कोई बाध्यकारी समय-सीमा थोप सकती है। इन दोनों फैसलों को मिलाकर देखें तो न्यायालय ने एक ओर कार्यपालिका के हस्तक्षेप से न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा की है, जबकि दूसरी ओर अपने अधिकार-क्षेत्र की सीमाएँ भी रेखांकित की हैं। न्यायाधिकरण संबंधी फैसले की बात करें तो 19 नवंबर को दिए गए 137 पृष्ठों के निर्णय में मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने साफ कहा है कि संसद पहले से रद्द किए गए प्रावधानों को मामूली बदलावों के साथ दोबारा पेश कर न्यायिक फैसलों को दरकिनार नहीं कर सकती। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि सरकार बार-बार उन्हीं प्रावधानों को अध्यादेश और फिर कानून के रूप में लागू करती रही, जिन पर न्यायालय स्पष्ट रूप से ऐतराज जता चुका था। यह प्रवृत्ति विधायी अवहेलना के रूप में व्याख्यायित की गई– अर्थात, बिना वास्तविक सुधार किए केवल प्रतीकात्मक परिवर्तन कर न्यायालय की बात को निष्प्रभावी करने का प्रयास। यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और संस्थागत मयार्दा को ठोस आधार देता है। न्यायाधिकरण सरकार के अंगों के विरुद्ध भी निर्णय लेते हैं; ऐसे में उनकी नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा-शर्तें यदि सरकार के नियंत्रण में हों, तो न्यायिक निष्पक्षता खतरे में पड़ सकती है। न्यायालय ने इस अधिनियम को शक्तियों के पृथक्करण और न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों का उल्लंघन करार देते हुए रद्द कर दिया। यह स्पष्ट संकेत है कि संसद कानून तो बना सकती है, लेकिन न्यायपालिका की मूलभूत स्वतंत्रता को नियंत्रण में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

दूसरा महत्वपूर्ण फैसला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भेजे गए संवैधानिक संदर्भ पर आया। न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न था– क्या राज्यपाल या राष्ट्रपति पर यह बाध्यता हो सकती है कि वे किसी बिल पर तय समय-सीमा में निर्णय दें? मुख्य न्यायाधीश गवई तथा न्यायमूर्ति सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पी.एस. नरसिंह और ए.एस. चंदुरकर की संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि न्यायालय राज्यपाल/राष्ट्रपति पर कोई निर्धारित समय-सीमा नहीं थोप सकता। यह स्पष्ट है कि "Deemed Assent" अर्थात समय बीतने पर बिल को स्वतः मंजूर मान लेने की अवधारणा असंवैधानिक है, क्योंकि यह कार्यपालिका की भूमिका को न्यायपालिका द्वारा हड़पने जैसा होगा। हाँ, यदि लंबे समय तक अनिश्चित देरी हो, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित हो, तो न्यायालय सीमित दायरे में यह निर्देश दे सकता है कि राज्यपाल अपनी जिम्मेदारी निभाएँ, लेकिन यह निर्देश विवेकाधिकार के उपयोग पर टिप्पणी नहीं करेगा। इस फैसले से दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली यह कि न्यायालय ने स्वयं पर अंकुश लगाते हुए साफ किया कि कार्यपालिका के संवैधानिक अधिकारों में दखल की सीमा तय है। दूसरी बात यह है कि राज्यपालों की ओर से बिलों को महीनों तक रोककर रखने की आलोचना को भी न्यायालय ने गंभीरता से लिया है और समाधान के रूप में सीमित न्यायिक समीक्षा का दरवाजा खुला रखा है। यह संतुलन स्थापित करना आसान नहीं था। एक ओर राज्यों–विशेषकर तमिलनाडु, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल ने तर्क दिया कि राज्यपालों द्वारा बिलों को रोकना लोकतंत्र-विरोधी है। दूसरी ओर, केंद्र ने कहा कि अदालतें समय-सीमा तय करके कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं दे सकतीं। अंततः न्यायालय ने वही रास्ता चुना जो भारतीय संविधान की आत्मा के अनुरूप है यानि संविधान ने समय-सीमा नहीं तय की है, इसलिए अदालत भी इसे तय नहीं करेगी। इन दोनों फैसलों में न्यायालय का स्वर पूरी तरह एक जैसा नहीं है। एक तरफ उसने संसद को तीखी चेतावनी दी, दूसरी तरफ उसने खुद अपनी सीमाओं को स्वीकार किया। यही दोहरी भूमिका भारतीय लोकतंत्र को संतुलित बनाती है। न्यायालय संदेश दे रहा है कि न्यायिक स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का आघात बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन संविधान में जो अधिकार अन्य अंगों को दिए गए हैं, उन पर न्यायपालिका कब्जा नहीं करेगी। इन फैसलों की समय-सीमा भी रोचक है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई 23 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। उनके बाद न्यायमूर्ति सूर्यकांत 24 नवंबर को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। इन दोनों महत्वपूर्ण संवैधानिक फैसलों पर गवई और सूर्यकांत दोनों की निर्णायक भूमिका भविष्य की न्यायिक दिशा के संकेत देती है– विशेषकर केंद्र-राज्य संबंधों और न्यायिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में। बहरहाल, संविधान ने भारत को एक संतुलित संरचना दी है–न्यायपालिका स्वतंत्र हो, कार्यपालिका जिम्मेदार हो और विधायिका जनता के प्रति उत्तरदायी हो। इन दोनों फैसलों ने इस संतुलन को और भी स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है। जहाँ न्यायालय ने संसद को बताया कि वह न्यायिक आदेशों को दरकिनार नहीं कर सकती, वहीं राज्यपालों और राष्ट्रपति की संवैधानिक गरिमा को भी मान्यता दी, यह कहते हुए कि समय-सीमा थोपना न्यायपालिका के अधिकार-क्षेत्र से बाहर है। इन फैसलों के साथ भारत का लोकतंत्र एक बार फिर यह साबित करता है कि संस्थाएँ तभी मजबूत होती हैं जब वे एक-दूसरे की सीमाओं और स्वतंत्रता का सम्मान करें। -नीरज कुमार दुबे

चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और कम हुई

बिहार में अभूतपूर्व जीत का श्रेय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एन.डी.ए.) को जाता है। नीतीश कुमार की व्यक्तिगत छवि और बिहार में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपनाई गई चतुर राजनीतिक रणनीति ने मिलकर गठबंधन को भारी बहुमत दिलाया। हालांकि चुनाव में भारी मतदान को देखते हुए गठबंधन की जीत लगभग तय थी लेकिन जीत की व्यापकता ने एन.डी.ए. के नेताओं को भी चौंका दिया होगा। लेकिन एन.डी.ए. का एक बाहरी सहयोगी, जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जिसका नाम लेना भी जरूरी है, वह था भारत का चुनाव आयोग। यह याद करना मुश्किल है कि आयोग ने कभी बिहार चुनावों में जिस तरह पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया है, वैसा पहले कभी किया हो। इसका सबसे बेशर्मी भरा काम उस खुलेआम रिश्वतखोरी पर आंखें मूंद लेना था जिसकी अनुमति राज्य सरकार ने चुनाव की पूर्व संध्या पर बिहार की 1.76 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए नकद देने की घोषणा करते समय दी थी। सरकार ने यह भी संकेत दिया कि यह राशि केवल अग्रिम राशि है और अगर सरकार सत्ता में वापस आती है तो इन महिलाओं को 6 महीने के भीतर उद्यम शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी।

10,000 रुपए की राशि और 2 लाख रुपए का वादा, राज्य के लोगों के लिए वास्तव में एक बड़ी राशि है, जहां प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम लगभग 30,000 रुपए प्रति वर्ष है जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह एक लाख रुपए प्रतिवर्ष से थोड़ा अधिक है। अपनी रणनीति के तहत एन.डी.ए. ने विधानसभा चुनावों की आधिकारिक घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने से कुछ दिन पहले ही इस योजना की घोषणा की। घोषणा का समय इस तरह से तय किया गया था कि चुनाव प्रचार के दौरान और मतदान से एक दिन पहले तक महिलाओं के बैंक खातों में धनराशि जमा हो जाए। इस योजना की घोषणा के समय के लिए चुनाव आयोग को दोषी नहीं ठहराया जा सकता लेकिन चुनावों की घोषणा के बाद नकदी हस्तांतरण पर रोक न लगाने के लिए वह निश्चित रूप से दोषी है। कोई भी चुनाव आयोग, जिसमें थोड़ा भी आत्मसम्मान होता, ऐसा करता। इसे एक चालू योजना के बहाने से पारित करना लोकतांत्रिक सिद्धांतों का मजाक उड़ाना था।

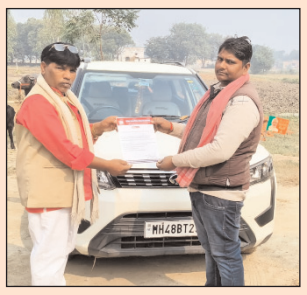

केवट सामाजिक सेवा फाउंडेशन के उत्तर प्रदेश अ.जा. अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र गौतम

मुंबई(उत्तरशक्ति)। केवट सामाजिक सेवा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलसीराम केवट के आदेशानुसार सुभाष चंद्र गौतम को फाउंडेशन के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष (अनुसूचित जाति) पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी नियुक्ति के बाद समाजसेवी व फाउंडेशन से जुड़े पदाधिकारियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर प्रिंस गुप्ता, अजय यादव (प्रधान), डॉ. संतोष यादव, शिव कुमार यादव, अमित भारती, आनंद गौतम, परविंद गौतम, धर्मपाल यादव, सूरज केवट (प्रधान), देव दत्त केवट, सुनील कुमार बिंद, बसंत कुमार बिंद, डॉ. रामचंद्र बिंद, दारा बिंद, शिवराज बिंद, राधेश्याम बिंद, महेश बिंद, राम आसरे बिंद, अशोक बिंद, अमर बहादुर पटेल, राय साहब बिंद सहित कई सामाजिक कार्यकताओं ने सुभाष चंद्र गौतम को शुभकामनाएं प्रेषित कीं। केवट सामाजिक सेवा फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया कि सुभाष चंद्र गौतम अपने अनुभव व कार्यकुशलता से संगठन को और अधिक मजबूत करते हुए समाज के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

हैदराबाद के वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला का मुंबई में सम्मान

मुंबई (उत्तरशक्ति)। हैदराबाद के वरिष्ठ पत्रकार एवं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद के मूल निवासी अजय शुक्ला इन दिनों मुंबई प्रवास पर हैं। शुक्रवार को वह सिद्धी विनायक मंदिर दादर पहुंचे जहां पर भगवान श्री गणेश के दर्शन, पूजन के पश्चात उन्हें सिद्धी विनायक मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष एवं मुंबई भाजपा के प्रदेश महामंत्री आचार्य पवन त्रिपाठी ने सम्मानित किया। इस मौके पर पवन त्रिपाठी ने कहा कि अजय शुक्ला जैसे व्यक्ति समाज में बहुत विरले ही मिलते हैं। हैदराबाद पहुंचने के बाद ऐसा एहसास नहीं होता कि हम अपने घर में नहीं है। सम्मान के साथ ही वह अपना कीमती समय भी हम लोगों को देते हैं। वह हम लोगों के लिए इतना सेवाभाव से कार्य करते हैं कि उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। इसके बाद भाजपा प्रदेश कार्यालय पर भाजपा प्रवक्ता महाराष्ट्र अजय पाठक ने वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला को सम्मानित किया। इस मौके पर श्री पाठक ने कहा कि उत्तर भारतीय समाज के लोग जिस भी क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में अपने कार्यों के जरिए अपनी पहचान बनाए हुए हैं। महाराष्ट्र हो या फिर तेलंगाना, यूपी बिहार के लोग अपने कार्यों और अपनी मेहनत, लगन से अपना इतिहास खुद ही लिख रहे हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हैदराबाद में शुक्ला जी से बहुत ही अच्छा काम किया है। हैदराबाद के हर क्षेत्र में शुक्ला जी ने अपनी पहचान अपने दम पर बनाया हुआ है। शानदार लेखनीय की वजह से हर क्षेत्र में लोग इन्हें न सिर्फ पहचानते हैं बल्कि इनका सम्मान करता है। इस मौके पर श्री शुक्ला ने आभार प्रकट किया। इस मौके पर , संपादक विजय सिंह कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह, पत्रकार अजय सिंह, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ओमप्रकाश चौहान समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

फायर ब्रिगेड अधिकारी आत्माराम मिश्र की मां का निधन

मुंबई (उत्तरशक्ति)। बृहन्मुंबई महानगरपालिका फायर ब्रिगेड के डिप्टी चीफ ऑफिसर (डीसीएफओ) आत्माराम मिश्र की माता कौशल्या जगदम्बा प्रसाद मिश्रा का निधन हो गया। वह 89 वर्ष की थी। शुक्रवार को काशी के मणिकर्णिका घाट पर डीसीएफओ आत्माराम मिश्र ने उन्हें मुखाग्नि दी। वह पिछले एक महीने से उम्र संबंधी बीमारी से पीड़ित थी।

डीसीएफओ आत्माराम मिश्र ने बताया कि वह उम्र संबंधी बीमारी से पीड़ित थी। गोरेगांव स्थित एक हॉस्पिटल में भर्ती थी। इलाज के दौरान ही उनका निधन हो गया। उसके बाद गुरुवार को ही शाम 5 बजे उनका पार्थिव शरीर मुंबई से विमान द्वारा उनके मूल गांव गोपालापुर, तहसील लंभुआ जिला सुल्तानपुर (उप्र) लाया गया जहाँ परिजनों और रिश्तेदारों ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। उसके बाद शुक्रवार को सुबह काशी में मणिकर्णिका घाट पर परिजनों और शुभचिंतकों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी।

कौशिल्या मिश्रा अपने पीछे पुत्र आत्माराम मिश्र समेत दो पौत्र एक पौत्री और तीन पुत्रियों का भरापूरा परिवार छोड़ गई हैं। उनके निधन पर लोगों ने परिवार के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है।

ऑक्सिलाइफ सैलून प्रोफेशनल की एडवांस फेशियल रेंज पेश

मुंबई/पटना। डाबर इंडिया के प्रीमियम सैलून स्किनकेयर ब्रांड, ऑक्सिलाइफ सैलून प्रोफेशनल ने आज तीन उन्नत सिंगल-यूज फेशियल ट्रीटमेंट किट - कोरियन ग्लास ग्लो, ग्लूटामिन व्हाइट रेडियंस और हाईड्रा बूस्ट रेडियंस - के लॉन्च की घोषणा की। इस लॉन्च को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनिका विश्वकर्मा के नेतृत्व में एक शानदार नए कैंपेन, 'रेडियंस वीजा पावर्ड बाय स्किनश्योरेंस विद ऑक्सिलाइफ' का समर्थन मिला है। विशेष रूप से सैलून के लिए तैयार किए गए, ये फेशियल ट्रीटमेंट, वैश्विक स्किनकेयर विज्ञान को प्रकृति-प्रेरित एक्टिव तत्वों के साथ मिश्रित करते हैं, ताकि तुरंत और लंबे समय तक चलने वाली चमक प्रदान की जा सके। इस रेंज का अनावरण करने के लिए, ऑक्सिलाइफ सैलून प्रोफेशनल ने एक साहसिक, डिजिटल-फर्स्ट टीजर एक्टिवेट किया, जिसकी जड़ें इसके केंद्रीय नैरेटिव, 'स्किनश्योरेंस विद ऑक्सिलाइफ' में थीं। इस कैंपेन ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनिका विश्वकर्मा के एक वायरल क्लिप के साथ देश भर में उत्सुकता जगाई, जिसमें उन्हें अपने फिनाले से पहले 'किसी महत्वपूर्ण चीज की तलाश में भागते हुए' देखा गया था। यह रहस्योद्घाटन एक खुलासा करने वाली फिल्म में हुआ, जहां मनिका ने अटकलों को संबोधित किया और ट्विस्ट दियाः मुझे वह मिल गया जो मैंने खो दिया था, मेरा 'रेडियंस वीजा', जो 'स्किनश्योरेंस विद ऑक्सिलाइफ' द्वारा संचालित है।

युवा महोत्सव के लोकनृत्य प्रतियोगिता में पालघर जिले का राज्यस्तर पर चयन

युवा शक्ति ही राष्ट्र का भविष्य : जिलाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड

पालघर(उत्तरशक्ति)। जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय, पालघर तथा मुंबई विभाग के उपसंचालक (क्रीड़ा व युवा सेवा) के संयुक्त तत्वावधान में, राजगुरु ह. म. पंडित विद्यालय सफाले तथा टीमा के सहयोग से विभागीय युवा महोत्सव 2025-26 का भव्य आयोजन बोईसर स्थित टीमा हॉल में किया गया। विभिन्न कला, कौशल और नवोपक्रम को प्रदर्शित करने वाले इस महोत्सव में युवाओं ने शानदार प्रतिभा दिखाई।

इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में प्रमुख अतिथि के तौर पर पालघर की जिलाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड उपस्थित रहीं। उन्होंने युवा प्रतिभाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि युवा ही देश का भविष्य हैं। क्रीड़ा के साथ-साथ कला, साहित्य, विज्ञान और नवाचार की ऊर्जा जीवन को समृद्ध बनाती है। हर युवक-युवती ने अपनी प्रतिभा को निखारते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सांस्कृतिक विभाग में समूह लोकनृत्य और समूह लोकगीत जैसे पारंपरिक कार्यक्रमों ने मंच की शोभा बढ़ाई। वहीं विज्ञान प्रदर्शन में छात्रों की वैज्ञानिक दृष्टि और कल्पनाशक्ति का प्रभावी प्रदर्शन देखने को मिला। चित्रकला, कथा-लेखन, कविता-लेखन और वक्तृत्व जैसी सर्जनात्मक प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने सहभागिता दर्ज की। पूरे कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षक, अभिभावकों व मान्यवरों का उत्स्फूर्त प्रतिसाद देखने को मिला। समारोप समारोह में जिला क्रीड़ा अधिकारी सुहास व्हनमाने, जिला शिक्षक महासंघ अध्यक्ष प्रमोद पाटील, प्राचार्या मधुमती कुलकर्णी, गिरीश इरनक, भक्ती आंब्रे, अमृत घाडगे, मयूर खोल्लम सहित सभी परीक्षक उपस्थित थे। प्रतियोगिताओं के परिणाम निम्न प्रकार रहे। कविता लेखन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्रिया राठोड पालघर, द्वितीय स्थान मृणाली पाटील, ठाणे तथा तृतीय स्थान पूजा पांडे, मुंबई उपनगर ने हासिल किया। कथालेखन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान ईशांत मेहरा, ठाणे, द्वितीय स्थान पूजा पांडेय मुंबई उपनगर तथा तृतीय स्थान मनाली चौधरी, मुंबई उपनगर ने अर्जित किया। वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आशुतोष शुक्ला, पालघर द्वितीय स्थान पूजा पांडेय, मुंबई उपनगर तथा तृतीय स्थान अंश राय, पालघर ने प्राप्त किया। चित्रकला प्रतियोगिता में कशिश गणेश तिखे, रायगड, द्वितीय स्थान विकास राजभर, ठाणे तथा तृतीय स्थान जीनल माच्छी, पालघर ने अर्जित किया। विज्ञान व तंत्रज्ञान प्रतियोगिता में प्रथम स्थान बी.एन. बांदोडकर सीनियर कॉलेज, ठाणे, द्वितीय स्थान बी.एन. बांदोडकर जूनियर कॉलेज, ठाणे तथा तृतीय स्थान होली चाइल्ड सीबीएससी स्कूल, रायगड ने हासिल किया। लोकगीत प्रतियोगिता में सी के टी कॉलेज पनवेल, रायगड, द्वितीय स्थान सह्याद्री कॉलेज जुचंद्र, पालघर तथा तृतीय स्थान इंदिरा गांधी विद्यालय, मुंबई उपनगर ने प्राप्त किया। लोकनृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान सह्याद्री महाविद्यालय, जुचंद्र, वसई, द्वितीय स्थान सी के टी कॉलेज पनवेल, रायगड तथा तृतीय स्थान बी.ए. बांदोडकर कॉलेज, ठाणे ने हासिल किया।

मीना ताई कांबळे का जन्मदिन समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न

मुंबई (उत्तरशक्ति)। विश्वस्त श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी तथा शिवसेना (शिंदे गुट) की वरिष्ठ नेत्या मीना ताई कांबळे का जन्मदिन बड़े उत्साह और सादर शुभेच्छाओं के साथ मनाया गया। प्रभादेवी स्थित जनसंपर्क कार्यालय में उन्हें शॉल और पुष्पगुच्छ देकर हार्दिक शुभकामनाएँ अर्पित की गईं। इस अवसर पर समाजसेवक एवं विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें परिवर्तन संघटना, भामला फाउंडेशन, सनातन सेना फाउंडेशन, शिवसेना (शिंदे गुट) तथा गृह संकुल इमारत महाराष्ट्र व मुंबई के प्रतिनिधि शामिल थे। विशेष रूप से समाजसेवक सुखबिंदर सिंह (लाला भाई), श्रद्धा गोरगे (ज्योतिष) सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी मीना ताई कांबळे को जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छाएँ दीं। मीना ताई कांबळे ने सभी आगंतुकों व शुभेच्छुकों का आभार व्यक्त किया तथा आगमन पर उनके लिए अल्पाहार की व्यवस्था की गई।

सहायक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय में मनाया गया अंतरराष्ट्रीय ट्रांसजेंडर स्मरण दिवस

पालघर(उत्तरशक्ति/अजीत सिंह)। विश्वभर में ट्रांसजेंडर समुदाय पर होने वाली हिंसा और अत्याचार के चलते अपनी जान गंवाने वाले व्यक्तियों की स्मृति को नमन करने तथा उनके अधिकारों के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर वर्ष 20 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय ट्रांसजेंडर स्मरण दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में सहायक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय, पालघर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में डॉ. भुवनेश्वर बोरकर उपस्थित रहे, जबकि ट्रांसजेंडर समुदाय के कई सदस्य भी बड़ी संख्या में पहुंचे। सहायक आयुक्त पांडुरंग वाबले ने पुष्पगुच्छ और पुस्तकें प्रदान कर अतिथियों का सम्मान किया। कार्यक्रम की शुरूआत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित कर और दीप प्रज्वलन से हुई। स्वागत भाषण में वाबले ने ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने आयुष्मान भारत कार्ड, ट्रांसजेंडर पहचान पत्र और केंद्र सरकार की ह्लरटक्छएह्व योजना के अंतर्गत उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहचान देना और उन्हें मतदान का अधिकार प्रदान करना सरकार की ज़िम्मेदारी है। इसके लिए उन्होंने सभी से ३३स्त्र२://३१ल्लरॅल्ली१.ङ्क्रिॐ.ङ्क ५.ल्ल/ पोर्टल पर पंजीकरण कर तुरंत पहचान पत्र प्राप्त करने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि पहचान पत्र प्राप्त होने पर ही मतदाता कार्ड सहित शिक्षा व अन्य सुविधाओं का लाभ निर्बाध रूप से मिल सकेगा। साथ ही समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को समाज कल्याण कार्यालय, पालघर में संपर्क करने का आग्रह किया। अध्यक्षीय भाषण में डॉ. भुवनेश्वर बोरकर, उपयुक्त, पशुसंवर्धन विभाग, पालघर ने ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों व कल्याण पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में डॉ. मधुवंती महाजन, श्री सदावर्ते (संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल कल्याण), तुषार डामसे (बहुजन कल्याण अधिकारी) तथा समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग और जिला जात प्रमाणपत्र पडताल समिति के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। अंत में उपस्थित सभी मान्यवरों एवं अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए चाय व अल्पाहार के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया।

कमलादेवी एज्युकेशनल ट्रस्ट द्वारा मुफ्त नेत्र शिविर

शांतीलाल संघवी आय इन्स्टिट्यूट मुंबई का विशेष योगदान

चेतन निर्मल संवाददाता

कल्याण (उत्तरशक्ति)। कल्याण पूर्व में कमलादेवी महाविद्यालय ने एक अनोखी पहल की है, जिसके तहत कल्याण पूर्व के विठ्ठलवाड़ी परिसर के नागरिकों के लिए मुफ्त मोतियाबिंद सर्जरी और संपूर्ण नेत्र रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन महाविद्यालय के संस्थापक सदानंद (बाबा) तिवारी और श्वेता तिवारी (पांडे) इनके द्वारा किया गया।

इस कार्यक्रम में लगभग 200 मरीजों ने भाग लिया और अपने नेत्र संबंधित समस्याओं का निराकरण किया।और 71 रुग्ण मोतीयाबंद के मिले उसमे से 42 लोगो का ओप्रेशन के लिये भेजा गया है. यह आयोजन न केवल नेत्र स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में नेत्र संबंधी सेवाएं प्रदान करने में भी सहायक होता है। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख अतिथियों में निलेश शिंदे शिवसेना शहर प्रमुख, कमलादेवी महाविद्यालय के अध्यक्ष सदानंद तिवारी, संस्था की खजांची श्वेता पांडे, समाज सेवक प्रकाश तरे,समाजसेक महादेव रायभोले और विशेष कार्यकारी अधिकारी मधुर म्हात्रे शामिल थे। यह आयोजन समाज में नेत्र स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में नेत्र संबंधी सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने की जव्हार तहसील के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक

पालघर(उत्तरशक्ति)। मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान के अंतर्गत जव्हार तहसील में जारी विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति का सविस्तर समीक्षा बैठक 21 नवम्बर को अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र शिंदे ने किया। इस अवसर पर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) अशोक पाटील, प्रभारी गटविकास अधिकारी संदेश दुमाडा तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

समीक्षा बैठक से पहले एसीईओ रवींद्र शिंदे ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, साकुर का दौरा कर स्वास्थ्य सुविधाओं, उपलब्ध स्टाफ तथा मरीजों को दी जा रही सेवाओं की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने मनरेगा के तहत शुरू किए गए विहिरी (कूप) निर्माण कार्य का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर कार्य की गुणवत्ता की जांच की और आवश्यक निर्देश दिए। इसी दौरान घरकुल योजनांतर्गत बन रहे घरकुलों की भी समीक्षा की गई। बैठक में घरकुल योजना, मनरेगा कार्य, पानीटंचाई निवारण उपाय, ग्रामपंचायत प्रशासन, सार्वजनिक शौचालय, तथा तहसील में चल रहे अन्य महत्वपूर्ण विकास प्रकल्पों पर सविस्तर चर्चा की गई। सभी विभागों को प्रलंबित कार्यों को गति देकर निर्धारित समय में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

जिला ग्रामीण विकास यंत्रणा उमेद अंतर्गत महिलाओं का 100 प्रतिशत स्वयं सहायता समूहों में समावेश कर उन्हें लखपति दीदी बनाने पर विशेष जोर देने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। इसके लिए त्वरित एवं प्रभावी नियोजन करने के आदेश दिए गये। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र शिंदे ने कहा कि जव्हार तहसील के सभी विकास कार्य तेज और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे हों, ताकि समृद्ध पंचायत राज अभियान में तहसील विशेष स्थान प्राप्त कर सके। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यक्षमता बढ़ाने और जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करने के निर्देश भी दिए।

बीएनएन कालेज में हर्षोल्लाश के साथ मनाया गया विश्व टेलीविजन दिवस

आचार्य सूरजपाल यादव

भिवंडी (उत्तरशक्ति)। पद्मश्री अण्णा साहेब जाधव भारतीय उन्नति मंडल द्वारा संचालित बीएनएन कालेज में हर्षोल्लाश से मनाया गया दूरदर्शन डे। इस अवसर पर संस्था के कार्याध्यक्ष बालकृष्ण काले ने कहा कि टेलीविजन समाज को दिशा देने वाला एक असरदार जरिया है जो दुनिया की ग्लोबल घटनाओं, शहरों, जगहों और हालात की जानकारी घर बैठे मिल जाती है। आज बदलते समय में भी टीवी की पकड़ मजबूत है और यह हमारी जिंदगी का एक जरूरी जरिया है। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार संजय भोईर, अभिनेता विनायक सिंह, प्रभारी डा. शशिकांत म्हालुंकर, उप प्राचार्य डा. सुधीर निकम, डा. निनाद जाधव, डीएल अहिरे आदि लोग उपस्थित थे। टेलीविजन ने दुनिया को करीब ला दिया है। इसकी वजह से ज्ञान का लेन-देन हो पाता है जिससे समाज को मजबूत बनाने में मदद मिली है।

आज के स्टूडेंट्स रंगीन जमाने के हैं, लेकिन पचास पार कर चुके हर किसी ने टेलीविजन के ब्लैक एंड व्हाइट जमाने को महसूस किया है उसे याद करते हुए कहा जो टेलीविजन उस समय कुछ लोगों के घरों में था वह आज हर किसी के घरों में पहुँच गया है। टेलीविजन सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है बल्कि समाज में नॉलेज, साइंस और अवेयरनेस का एक जरूरी टूल है। हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं यह जरूरी है ऐसा सीनियर जर्नलिस्ट संजय भोईर ने कहा। अभिनेता विनायक सिंह ने अभिनय के तीन सिद्धांतों को समझाया और छात्रों के साथ अभिनय का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में प्रा. प्रमोद शेवाले, प्रा. जरमिन मोमिन, प्रा. अंकुश चव्हाण, प्रा. गणेश पानझाड़े, प्रा. प्रियंका जाधव, प्रा. नीलम सेन, प्रा. अक्षय भोईर, प्रा. पूजा देशमुख, प्रा. नेहा आलशी, प्रो. सैफ अंसारी, प्रा. चार्मी गोंडालिया और बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन छात्रा दिव्या मेहता और सबा मोमिन ने किया और आभार प्रो. शिवम भानुशाली ने प्रकट किया।

भांडुप में भव्य पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन

मुंबई। दीना बामा पाटिल की 91वीं जयंती के अवसर पर, दीना बामा पाटिल पुस्तकालय एवं अध्ययन केंद्र में पूर्व विधायक एवं विभागाध्यक्ष रमेश कोरगांवकर द्वारा एक पुस्तक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर संस्था की मुख्य न्यासी पल्लवी पाटिल और युवा सेना कार्यकारिणी सदस्य राजोल संजय पाटिल उपस्थित थे।

बता दें कि मजदूर नेता एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय दीना बामा पाटिल की 91वीं जयंती 24 नवंबर को है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। पठन संस्कृति को बढ़ावा देने और उसे बढ़ावा देने के लिए, भांडुप रेलवे स्टेशन स्थित दीना बामा पाटिल एस्टेट के पास हर वर्ष ऐसी प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी यह प्रदर्शनी 14 से 30 नवंबर तक सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक सभी के लिए खुली गई है। आयोजक पल्लवी पाटिल ने पुस्तक प्रेमियों से इस प्रदर्शनी में आने की अपील की है। पुस्तक प्रदर्शनी के पहले दिन बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और बड़ी मात्रा में पुस्तकें खरीदीं। स्कूली छात्रों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कई गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें और देश-विदेश के प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकें इस प्रदर्शनी में रखी गई हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के साथ-साथ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल पर पुस्तकों के साथ-साथ व्यवसाय कैसे चलाया जाए, भोजन को स्वादिष्ट कैसे बनाया जाए, बच्चों में मूल्यों का संचार कैसे किया जाए, जैसे विभिन्न विषयों पर पुस्तकें इस प्रदर्शनी में रखी गई हैं। इस बीच, 28 और 30 नवंबर को शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक पुस्तक विनिमय उत्सव का आयोजन किया गया है । इस उत्सव में पढ़ी गई पुस्तक दान कर सकते हैं और अपनी पसंद की पुस्तक ले सकते हैं।

मुंबई के मजदूरों की आवाज, मजदूर नेता, विधायक स्वर्गीय दीन बामा पाटिल की जयंती के अवसर पर भांडुप में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, उत्तर पूर्व मुंबई महाविकास आघाड़ी के सांसद संजय दीना पाटिल के मार्गदर्शन में पल्लवी पाटिल ने दीना बामा पाटिल पुस्तकालय एवं अध्ययन केंद्र की शुरूआत की।

वैल्यू 360 कम्युनिकेशंस को प्रस्तावित एसएमई आईपीओ के लिए मिला एनएसई से इन-प्रिंसिपल अप्रूवल

मुंबई। वैल्यू 360 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने आज घोषणा की कि उसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) से अपने इक्विटी शेयरों को एनएसई के इमर्ज प्लेटफॉर्म (ठरए ऐंॐ) पर लिस्ट करने के लिए इन-प्रिंसिपल अप्रूवल प्राप्त हुआ है। यह मंजूरी कंपनी की ओर से सभी नियामकीय आवश्यकताओं और आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी करने के अधीन है। इन-प्रिंसिपल अप्रूवल, कंपनी के ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखिल करने के बाद एक महत्वपूर्ण नियामकीय उपलब्धि है। यह अप्रूवल इश्यू की पुष्टि नहीं होता और न ही पेश किए जाने वाले सिक्योरिटीज की स्वीकृति का संकेत देता है। अंतिम मंजूरी तब मिलेगी जब कंपनी रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (आरएचपी) दाखिल करेगी और एनएसई व सेबी द्वारा निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करेगी। वैल्यू 360 कम्युनिकेशंस एक इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशंस कंपनी है, जो पब्लिक रिलेशंस, डिजिटल कम्युनिकेशन, क्रिएटिव स्ट्रैटेजी और रेप्यूटेशन मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में विभिन्न ब्रांड्स के साथ काम करती है। कंपनी की प्रस्तावित लिस्टिंग का उद्देश्य अपनी ग्रुप कंपनियों की क्षमताओं को मजबूत करना और अपने सर्विस ईकोसिस्टम का विस्तार करना है।

उत्तरशक्ति
* संपादकः ओमप्रकाश प्रजापति
* उप संपादकः प्रेम चंद मिश्रा
*प्रबंध संपादकः डा. शेषधर बिन्द
उपरोक्त सभी पद अवैतनिक है।
पत्राचार कार्यालय :
उत्तरशक्ति (हिंदी दैनिक)
मुंबई-पुणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5, ए-337 ट्रक टर्मिनल डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल ऑटाप हिल वडाला, मुंबई-37
मो.- 9554493941
email ID- uttarshaktinews@gmail.com

स्वामी: शरद फागुराम प्रजापति, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति द्वारा सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, यूनिट क्रमांक 4, तल मजला, एन.के. इंडस्ट्रियल स्टेट, आरे रोड, प्रवासी इंडस्ट्रियल एस्टेट, जवल, गेट क्रमांक 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-400063, महाराष्ट्र से मुदित एवं के-4, रूम नं. 8, ग्राउंड फ्लोर न्यू समता सहकारी को.ऑ. हां. सोसाइटी, एमएमआरडीए कॉलोनी कंजूरमार्ग (वेस्ट), जिला मुंबई- 400078, महाराष्ट्र से प्रकाशित। RNI NO. MAHHIN/2018/76092 * संपादक- ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति, समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के लिए उत्तरदाई तथा इससे उत्पन्न समस्त विवाद मुंबई न्यायालय के अधीन होंगे।
पत्राचार कार्यालय: मुंबई-पुणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5 ए-337 ट्रैक टर्मिनल, डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल, ऑटाप हिल, वडाला मुंबई -37, मो.- 9554493941 email ID- uttarshaktinews@gmail.com

अवैध शराब पर ताबड़तोड़ छापे, ईंट भट्ठों से लेकर ठेकों तक सख्त निरीक्षण

शाहगंज में आबकारी विभाग की धाक, कच्ची व अवैध शराब पर जीरो टॉलरेंस

प्रभारी निरीक्षक रेनू देवी बोलीं, मानक से बाहर कारोबार मिलने पर होगी कार्रवाई

शाहगंज,जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जिले में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए

आबकारी विभाग ने शुक्रवार को नगर तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा अभियान चलाया। प्रभारी निरीक्षक रेनू देवी के नेतृत्व में विभागीय टीम ने न सिर्फ शराब के ठेकों का औचक निरीक्षण किया, बल्कि उन ईंट भट्ठों पर भी छापेमारी की, जिनके बारे में कच्ची शराब बनाने की सूचनाएँ प्राप्त हुई थीं।

अचानक हुई कार्रवाई को देखते हुए क्षेत्र में हलचल मच गई। टीम ने शहर के विभिन्न शराब ठेकों पर आयझव्यय रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर और लाइसेंस संबंधी दस्तावेजों की गहन जांच की। निरीक्षण के दौरान सभी अभिलेख संतोषजनक पाए जाने पर दुकानदारों को निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार बिक्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

वहीं, सोंगर, चिरैयाडीह समेत कई स्थानों पर स्थित ईंट भट्ठों पर छापेमारी की गई। कच्ची शराब के निर्माण को लेकर प्राप्त शिकायतों की पुष्टि करने के लिए टीम ने स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। हालांकि कहीं भी अवैध शराब से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली, जिस पर प्रभारी निरीक्षक ने संतोष जताया।

प्रभारी निरीक्षक रेनू देवी ने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मानक के विपरीत शराब बेचना, कच्ची शराब बनाना या अवैध कारोबार को शरण देना किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सभी दुकानदारों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। यदि कहीं भी नियम विरुद्ध गतिविधि पाई गई, तो संबंधित के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने कहा।

आबकारी विभाग की इस कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं आम जनता विभाग की तत्परता की सराहना कर रही है। उक्त मौके पर कांस्टेबल मुनेश तिवारी, सुरेन्द्र सिंह, महेंद्र पाल एवं महेंद्र सरोज प्रमुख रूप से टीम में शामिल रहे।

48वीं ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का रामपुर में हुआ भव्य शुभारंभ

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। रामपुर ब्लॉक में आयोजित 48 वीं रामपुर ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ श्री सहदेव इंटर कॉलेज, भोड़ा के मैदान में किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, डॉ. गोरखनाथ पटेल द्वारा फीता काटकर किया गया।

मुख्य अतिथि ने बच्चों के अंदर खेल के प्रति दिखे उत्साह और जोश की प्रशंसा करते हुए कहा कि खेल से बच्चों में अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित होती है। उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया।

बच्चों द्वारा बनाई गई सुंदर रंगोली का भी निरीक्षण किया गया। सबसे सुंदर रंगोली बनाने वाले प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया गया।

खंड शिक्षा अधिकारी, रामपुर अश्विनी सिंह ने खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

श्री सहदेव इंटर कॉलेज, भोड़ा के प्रधानाचार्य एवं समस्त शिक्षक/शिक्षिकाओं के सहयोग से प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न हुई। ग्राम सभा के ग्राम प्रधान द्वारा भी प्रतिभागी बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया।

प्राथमिक विद्यालय कबड्डी (बालिका वर्ग) का फाइनल मैच न्याय पंचायत बनिडीह बनाम पृथ्वीपुर के बीच हुआ। प्राथमिक विद्यालय कबड्डी (बालक वर्ग)फाइनल मैच पृथ्वीपुर बनाम नोनारी के बीच हुआ। उच्च प्राथमिक विद्यालय कबड्डी (बालक वर्ग) ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

दौड़ प्रतियोगिता में प्राथमिक विद्यालय 50 मीटर दौड़ (बालक वर्ग) में अरी के हिमांशु ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 50 मीटर दौड़ (बालिका वर्ग) में नैंसी ने प्रथम स्थान, 100 मीटर दौड़ (बालिका वर्ग) में नैंसी ने प्रथम स्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय 100 मीटर दौड़ (बालिका वर्ग) रितु ने प्रथम स्थान, 200 मीटर दौड़ (बालक वर्ग) विजय बनवासी ने प्रथम, 400 मीटर दौड़ (बालक वर्ग) विशाल ने प्रथम 600 मीटर दौड़ (बालक वर्ग) में विपिन पटेल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में कबड्डी, खो-खो, दौड़, वॉलीबॉल, बैडमिंटन सहित विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया।

खेल व्यायाम शिक्षक अमित सोनकर, टीम मैनेजर अनुराग सत्यार्थी, टी.पी.एल. स्पोर्ट्स टीम, सभी टीम कोच एवं अध्यापकों का योगदान सराहनीय रहा। बच्चों ने बढ़-चढ़कर प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और उत्कृष्ट खेलभावना का प्रदर्शन किया।

पुलिस लाइन में प्रचलित रिक्रूट आरक्षियों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में गोष्ठी हुआ आयोजन

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन स्थित बहुउद्देशीय हॉल में रिक्रूट आरक्षियों

को प्रचलित प्रशिक्षण व आउटडोर व इनडोर विषयों के संबन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। दिनांक 21 नवम्बर 2025 को पुलिस लाइन, जौनपुर में पुलिस अधीक्षक जौनपुर द्वारा प्रचलित रिक्रूट आरक्षीयों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में गोष्ठी आयोजित कर आउटडोर व इनडोर प्रशिक्षण सम्बंधित जानकारी प्रदान की गई। गोष्ठी के दौरान पुलिस अधीक्षक ने सभी प्रशिक्षुओं के स्वास्थ्य, प्रशिक्षण की स्थिति तथा अन्य व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की और उनके समाधान हेतु सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किया गया तथा गोष्ठी में प्रशिक्षुओं को साइबर अपराध, सोशल मीडिया से संबंधित सतर्कता, साइबर सुरक्षा, आधुनिक तकनीकी उपकरणों के उपयोग तथा व्यवहारिक पुलिसिंग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई तथा प्रशिक्षुओं को नैतिक मूल्यों, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा एवं जनसेवा की भावना के साथ कार्य करने हेतु प्रेरित किया गया, सम्मेलन के दौरान प्रशिक्षुओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा अपने विचार एवं समस्याएं साझा कीं। पुलिस अधीक्षक ने रिक्रूट आरक्षियों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे प्रशिक्षण के प्रत्येक पहलू को गंभीरता से ग्रहण करें ताकि वे भविष्य में एक सक्षम, संवेदनशील एवं तकनीकी रूप से दक्ष पुलिस कर्मी के रूप में समाज की सेवा कर सकें। सोशल मीडिया सेल जनपद-जौनपुर।

फर्जी डीएल, आरसी, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, श्रम कार्ड बनाने के आरोप में 2 गिरफ्तार

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। फर्जी व जालसाजी तरीके से डीएल, आरसी,

आधार कार्ड, फिटनेस प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, श्रम कार्ड बनाने वाले 02 आरोपी गिरफ्तार। जालसाजी में प्रयुक्त कंम्यूटर, सी.पी.यू. व मोबाईल बरामद। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर विश्वनाथ प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में चेकिंग के दौरान मोहल्ला ओलन्दगंज के पास से फर्जी व जालसाजी तरीके से डीएल, आरसी, आधार कार्ड, फिटनेश प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, श्रम कार्ड बनाने वाले 02 नफर आरोपीगण राकेश यादव उर्फ चानू पुत्र सभाजीत यादव निवासी ताहिरपुर थाना सिकरारा जनपद जौनपुर, विवेक निषाद पुत्र मनोज निषाद उमरपुर हरबंधनपुर थाना कोतवाली जौनपुर को फर्जी तरीके से डी0एल0, आर0सी0, आधार कार्ड, फिटनेश प्रमाण पत्र, अयुष्मान कार्ड बनाने मे प्रयुक्त कंम्यूटर, एक सी.पी.यू म कार्ड बनाने के कुछ कागजात, 02 अदद मोबाईल व 4000/ नगद रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामद अवैध व फर्जी तरीके से डी0एल0, आर0सी0 आदि बनाने में प्रयुक्त एक कम्प्यूटर, एक सी0पी0यू0 के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 352/25 धारा 319(2),318(1), 338, 336 (3),340(2) बीएनएस पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

जौनपुर जेल में बंदी की मौत, परिजनों ने जांच की मांग को लेकर किया हंगामा

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जिला जेल में रविवार को एक बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान शहर कोतवाली क्षेत्र के तारापुर तकिया निवासी मो. सुफियान (24) के रूप में हुई है, जो अपनी पत्नी की मौत के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में था।

मामले की जानकारी मिलने पर परिजन जेल गेट पहुंचे और मृत्यु की परिस्थितियों को लेकर नाराजगी जताते हुए जांच की मांग करने लगे। परिजनों का कहना है कि उन्हें सुफियान की हालत की सूचना समय पर नहीं दी गई। उनका दावा है कि सुफियान की मौत दोपहर करीब 12:35 बजे हुई, जबकि उन्हें जानकारी शाम 4 बजे मीडिया माध्यम से मिली।

परिजनों ने यह भी कहा कि उन्हें घटना की पूरी सच्चाई सामने आने की उम्मीद है और प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं परिवार के कुछ सदस्यों ने मौत को लेकर अभियुक्त पक्ष और कुछ जेल कर्मियों की भूमिका की जांच कराए जाने की मांग की है।

जेल प्रशासन का कहना है कि मामले में निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का स्पष्ट कारण सामने आएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर पैसे लेने वाला एक आरोपी गिरफ्तार

सिकरारा, जौनपुर (उत्तरशक्ति)। नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर पैसे लेने वाला वांछित आरोपी गिरफ्तार। प्रभारी निरीक्षक सिकरारा उदयप्रताप सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 ओम प्रकाश यादव मय हमराही गणों के द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर दिनांक 20.11.2025 को थाना

स्थानीय के मुकदमों में वांछित आरोपी मंगला प्रसाद यादव पुत्र दयाशंकर यादव निवासी जौंगीपुर थाना मडियाहू जौनपुर को गिरफ्तार कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है आरोपी के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

नाम व पता आरोपीः मंगला प्रसाद यादव पुत्र दयाशंकर यादव निवासी जौंगीपुर थाना मडियाहू जौनपुर उम्र करीब 28 वर्ष।

अपराधिक इतिहासः मु0अ0सं0 262/23 धारा 419/420/467 /471/ 504/406/120बी/506 भादवि थाना सिकरारा जनपद जौनपुर। मु0अ0सं0 139/24 धारा 419/420/467/ 471/504/506/120 बी/ 406 भादवि थाना सिकरारा जनपद जौनपुर।

मडियाहूँ की साइबर हेल्प डेस्ट टीम ने गुम हुई मोबाइल को बरामद कर स्वामी को किया सुपुर्द

मडियाहूँ, जौनपुर (उत्तरशक्ति)। थाना मडियाहूँ की साइबर हेल्प डेस्ट टीम ने उएक्फ़पोर्टल पर मोबाइल गुम होने की दर्ज शिकायत पर आवेदक का मोबाइल बरामद सुपुर्द कर दिया। थाना मडियाहूँ पुलिस की साइबर हेल्प डेस्क की टीम द्वारा उएक्फ़ पोर्टल पर मोबाइल मुग होने की दर्ज

शिकायत पर अथक प्रयास कर आवेदक थाना मडियाहूँ जनपद जौनपुर का मोबाइल OPPO A76 Android फोन बरामद कर नियमानुसार आवेदक उपरोक्त को सुपुर्द किया गया।

बीपीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पोर्टल 25 तक खुला

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर द्वारा सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित बीपीएड पाठ्यक्रम (सत्र 2025झ्र2027) की रिक्त सीटों के सापेक्ष सीधे प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय ने सूचना जारी की है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया है कि सीधे प्रवेश के लिए समर्थ पोर्टल 20 नवम्बर 2025 से 25 नवम्बर 2025 तक खुला रहेगा। पूर्व में समर्थ पोर्टल पर आवेदन कर चुके और अब तक प्रवेश से वंचित अभ्यर्थी इच्छानुसार सम्बद्ध महाविद्यालयों में सीधे प्रवेश ले सकते हैं। वहीं, जो अभ्यर्थी पूर्व में आवेदन प्रक्रिया से वंचित रह गए थे, वे भी समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण एवं आवेदन फार्म भरकर सीधे प्रवेश पा सकते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि वे समर्थ पोर्टल के माध्यम से अर्ह अभ्यर्थियों का पंजीकरण कराकर एवं आवेदन फार्म भरवाकर प्रवेश प्रदान करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि प्रवेश केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का किया जाए जो एनसीटीई तथा विश्वविद्यालय द्वारा जारी बीपीएड प्रवेश नियमावली के मानकों के अनुरूप अर्ह हों। यदि कोई अभ्यर्थी नियमावली के अनुसार अर्ह नहीं पाया जाता है तो उसकी प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा जांचोपरांत निरस्त भी की जा सकती है। बीपीएड प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित सभी विवरण, समर्थ पंजीकरण/आवेदन फार्म तथा शुल्क जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

कोतवाल समेत 7 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश

वीडियो बनाने से नाराज होकर रची साजिश, प्रेमिका से कराया हत्या के प्रयास का मुकदमा

आजमगढ़(उत्तरशक्ति)। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यवीर सिंह की अदालत ने देवगांव थाने के तत्कालीन कोतवाल विनय कुमार मिश्रा, दो सब-इंस्पेक्टर और चार कांस्टेबलों सहित सात पुलिसकर्मियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर मुलजिम पर कातिलाना हमला करने के

गंभीर आरोपों की जांच के बाद दिया। मामले की वादिनी लीलावती (निवासी रजमो, थाना देवगांव) ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में दिए प्रार्थना-पत्र में आरोप लगाया कि उनका बेटा विकास कुमार सामाजिक व राजनीतिक साजिश का शिकार बनाया गया। 25 अप्रैल 2024 को तत्कालीन इंस्पेक्टर विनय कुमार मिश्रा अपने हमराहियों के साथ उनके घर आए थे। वहां विकास से कहासुनी हो गई, जिसका लीलावती ने वीडियो बना लिया। इस बात से क्रुद्ध होकर इंस्पेक्टर मिश्रा ने साजिश रची और विकास की प्रेमिका से उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया। लीलावती के अनुसार, 1 मई 2024 को दिन में करीब 4 बजे एक बरक्षा कार्यक्रम से पुलिस टीम ने विकास को उठा लिया। इसकी सूचना उन्होंने तुरंत डायल-100 और पुलिस के उच्चाधिकारियों को दी। आरोप है कि रात करीब 11 बजे इंस्पेक्टर विनय कुमार मिश्रा, पल्हना चौकी इंचार्ज सुल्तान सिंह, उपनिरीक्षक रुद्रभान पांडेय, हेड कांस्टेबल शुभ नारायण, कांस्टेबल संजय दुबे, गुलाब यादव, विनोद सरोज व अन्य पुलिसकर्मियों ने मिलकर विकास को गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की। इससे पहले सीजेएम कोर्ट ने लीलावती का प्रार्थना-पत्र खारिज कर दिया था, लेकिन सत्र न्यायालय में दाखिल निगरानी याचिका पर सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट नंबर-1) अजय कुमार शाही ने निगरानी स्वीकार कर मामला पुनः सुनवाई के लिए सीजेएम कोर्ट को भेज दिया। लंबी सुनवाई के बाद सीजेएम सत्यवीर सिंह ने प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुए सभी आरोपित पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित किया।

स्कॉर्पियो की टक्कर से होटल कर्मी की मौत

बेटी की शादी से पहले परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

वाराणसी(उत्तरशक्ति)। जनपद के कैंट थाना क्षेत्र के डीआईजी पीएसी आवास के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने स्कूटी सवार राजेश गोंड (निवासीझ इमलिया घाट, फुलवरिया) को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। राजेश शहर के एक होटल में हाउस कीपिंग स्टाफ थे और ड्यूटी पर जा रहे थे। मृतक की पत्नी शीला और परिवार बेसुध हैं, क्योंकि उनकी बड़ी पुत्री अंजली उर्फ बिन्नी की शादी 25 नवम्बर को होनी थी। छोटी पुत्री मिनी भी परिवार में है। कैंट प्रभारी शिवाकांत मिश्रा ने शव

को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए स्कॉर्पियो व चालक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

विश्वविद्यालयों की दिशा और दशा में हुआ गुणात्मक बदलावः डॉ.रसिकेश

◆ एच.आर.डी.विभाग मनाया गया राज्यपाल का जन्मदिन

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के एच.आर.डी. विभाग में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल का जन्मदिन उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विभागाध्यक्ष डॉ. रसिकेश ने किया। उन्होंने अध्यक्षीय उद्बोधन में राज्यपाल के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनकी पुस्तक 'चुनौतियां मुझे पसंद हैं' का उल्लेख करते हुए कहा कि किस प्रकार उन्होंने उच्च शिक्षा में अनेक नवाचार लागू कर विश्वविद्यालयों की दिशा और दशा में गुणात्मक परिवर्तन किया है।

मुख्य वक्ता श्रेया सिंह ने राज्यपाल के जीवन यात्रा पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 21 नवम्बर 1941 को गुजरात के मेहसाणा जिले में जन्मी श्रीमती आनंदी बेन पटेल आज महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत और सशक्त रोल मॉडल हैं। उनके संवेदनशील प्रशासन का ही परिणाम है कि राज्य

विश्वविद्यालयों में सर्वाधिक महिला कुलपतियों की नियुक्ति कर उन्होंने महत्वपूर्ण मिसाल कायम की है।

प्राध्यापक अनुपम कुमार ने राज्यपाल के दीघार्यु जीवन की कामना करते हुए कहा कि नैक, एनआईआरएफ और क्यूएस रैंकिंग में सुधारे हेतु उनकी प्रेरणा से विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन संभव हुआ है। कार्यक्रम में छात्रा निक्की ने राज्यपाल पर आधारित ऊर्जा से भरपूर कविता का पाठ कर सभी को प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त अमृता, युगांत, श्रेया सिंह, अन्नू पांडे और अवंतिका ने भी राज्यपाल के योगदान और कार्यों को विस्तार से प्रस्तुत किया।

कार्यक्रम में डॉ. प्रवीण मिश्रा, खुशी सिंह, अमृता, संजना मिश्रा, दिव्यांशु सिंह, निधि सिंह, अन्नू पांडेय, आस्था सिंह सहित एच.आर.डी. विभाग के सभी छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

रेलवे की वेबसाइट पर पुराने कोड BSBS के स्थान पर 1 दिसम्बर से नया कोड BNRS दिखेगा

वाराणसी (उत्तरशक्ति)। बनारस स्टेशन यात्रा के लिए टिकट बुक करते समय यात्रियों को आरक्षण काउंटरों और रेलवे की वेबसाइट पर पुराने कोड BSBS के स्थान पर नया कोड BNRS दिखेगा, दिसंबर से लागू हो जाएगा।

बनारस स्टेशन से/तक की यात्रा के लिए टिकट बुक करते समय यात्रियों को आरक्षण काउंटरों, NTES, या IRCTC की वेबसाइट पर पुराने कोड इरइर के स्थान पर नया कोड इटफ्र अंकित करना होगा। चार साल पहले 15 जुलाई 2021 को मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया गया था।

अलग स्वरूप में दिखेगा बनारस रेलवे स्टेशनः यह रेलवे स्टेशन अब अपनी विश्वस्तरीय सुविधाओं और शानदार वास्तुकला के लिए जाना जाता

है, जो इसे किसी एयरपोर्ट या बड़े कॉर्पोरेट कार्यालय जैसा स्वरूप प्रदान करती है. स्टेशन पर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के साथ ही संस्कृत में बनारस भी लिखा गया है, जो पुरातन काशी की संस्कृति को दर्शाता है।

बनारस शब्द में मिठासः पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि मुख्यालय नए नाम पर मंजूरी मिलने से लोगों ने काफी प्रसंन्नता जताई है। डा. संपूणानंद के कार्यकाल में शहर का नाम बनारस से बदलकर वाराणसी कर दिया गया था। इस कवायद से एक बार पुनः बनारस की प्रमाणिकता को बल मिलेगा ल बनारस शब्द में मिठास है। मंडुआडीह स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों में भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी। बाहर से आने वाले लोग यहां की पौराणिकता का बोध कर सकेंगे।

चोरी गयी मोटरसाइकिल को नेवढिया पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया बरामद

नेवढ़िया, जौनपुर (उत्तरशक्ति)। चोरी की गयी मोटरसाइकिल को नेवढिया पुलिस द्वारा 24 घंटे के भीतर किया गया बरामद ' आज दिनांक 21.11.25 को थानाध्यक्ष नेवढिया राजाराम के नेतृत्व मे चौकी प्रभारी सीतमसराय उ0नि0 शिवभंजन प्रसाद मय हमराह द्वारा थाना नेवढ़िया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 248/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस मे चोरी मे वाँछित आरोपी अमित उर्फ मुन्ना गोड पुत्र रामचरितर गोड नि0 गोपीपुर भुसेहरा थाना मडियाहू जौनपुर उम्र करीब 42 वर्ष को मुखबीर की सूचना पर बर्राह पुलिया से गदनपुर की तरफ जाने वाले रास्ते समय करीब 10.50 बजे प्रातः गिरफ्तार किया गया ' आरोपी के कब्जे से 01 चोरी की लीओ होन्डा मोटर साइकिल बरामद किया गया '

आरोपी को मा0 न्यायालय भेजा गया, आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरणः दिनांक 20.11.2025 को वादी मुकदमा रमेश पुत्र लालमन राजभर निवासी ग्राम उसराँव जीतापुर थाना नेवढिया जिला जौनपुर मो0-7738165099 सूचना दिया कि गौरी शंकर महादेव मन्दिर से 200 मीटर पहले ग्राम दुहावर मे एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरी मोटर साइकिल हीरोहोन्डा नं0-यूपी62सीडी 8463 चोरी करके भाग गया है। वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 248/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस का अभियोग बनाम अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

क्षेत्राधिकारी केराकत चन्दवक थाने का किया त्रैमासिक निरीक्षण

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। पुलिस अधीक्षक, जौनपुर के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी केराकत, अजीत रजक द्वारा थाना चन्दवक का त्रैमासिक निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक, जौनपुर के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी केराकत अजीत रजक द्वारा आज थाना चन्दवक का त्रैमासिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर, सीसीटीवी कंट्रोल रूम, मालखाना, शस्त्रागार, हवालात, कार्यालय, मैस एवं विभिन्न अभिलेखों का बिंदुवार निरीक्षण कर उनकी स्थिति का आकलन किया। क्षेत्राधिकारी ने साफ-सफाई, अभिलेखों

के उचित संधारण, सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता, मालखाना व शस्त्रागार की सुरक्षा व्यवस्था तथा हवालात प्रबंधन के संबंध में संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने थाना परिसर में आगंतुकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं एवं सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने हेतु भी निर्देशित किया।

तिलक समारोह में शामिल हुए उत्तर यादव युवा समाज के पदाधिकारी

जौनपुर। उत्तर यादव युवा संघ के राष्ट्रीय सचिव जितेन्द्र जगरदेव यादव के जौनपुर स्थित केराकत आवास पर आज एक विशेष अवसर पर कई सम्मानित अतिथियों का आगमन हुआ। उत्तर प्रदेश सपा प्रवक्ता राकेश अहीर, जिला पंचायत सदस्य संतोष यादव तथा गुड्डू यादव तिलक समारोह में शामिल हुए और अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इनके आगमन से पूरे परिवार एवं क्षेत्र में हर्ष का वातावरण व्याप्त रहा और जितेन्द्र जगरदेव यादव के परिजनों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। इस अवसर पर क्षेत्र के कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। जिनमें प्रोफेसर महेंद्र यादव, देवेन्द्र यादव, जोगेंद्र यादव, धर्मेन्द्र यादव, रविन्द्र यादव, राम आसरे यादव, राजबहादुर यादव, कन्हैया लाल यादव, अशोक यादव, एडवोकेट अभीषेक यादव, राजेश यादव, रिंकू यादव तथा अन्य समाजसेवी एवं सम्मानित नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ।

उत्तर यादव युवा संघ के पदधिकारी ने सामाजिक मुद्दों पर की चर्चा

जफराबाद (जौनपुर)। उत्तर यादव युवा संघ के राष्ट्रीय सचिव जितेन्द्र जगरदेव यादव के बीबीपुर स्थित आवास पर गुजरात से आए संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सौहार्दपूर्ण मुलाकात की और संगठन को मजबूत बनाने पर विशेष चर्चा की। इस अवसर पर गुजरात प्रदेश अध्यक्ष एवं सपा गुजरात प्रदेश सचिव हरिराम कन्हैया लाल यादव, गुजरात प्रदेश उपाध्यक्ष विजय यादव, वलसाड जिला कोषाध्यक्ष किशन यादव, तथा तलासरी सलाहकार एवं उद्योगपति पप्पू यादव ने उपस्थित होकर जितेन्द्र यादव का उत्साहवर्धन किया। वरिष्ठ पदाधिकारियों के आगमन से गांव में भी हर्ष का माहौल रहा। आगंतुक नेताओं ने कहा कि संगठन युवाओं की ऊर्जा और एकता के बल पर निरंतर प्रगति कर रहा है तथा समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सभी मिलकर कार्य करते रहेंगे। कार्यक्रम में प्रोफेसर महेंद्र यादव, शिक्षक देवेंद्र यादव, धर्मेंद्र यादव, रविंद्र यादव, राम आसरे यादव, राजबहादुर यादव, अशोक यादव सहित क्षेत्र के कई लोग उपस्थित रहे। यह मुलाकात राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर संगठन को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

बसुई नदी पर मिनी पुल निर्माण की मांग को लेकर हर गांव में ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जौनपुर बरसठी धनापुर कुंदनपुर के बीच बसुई नदी पर मिनी पुल निर्माण की मांग को लेकर शुक्रवार को ग्रामीणों ने जज सिंह अन्ना के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मछलीशहर-मडियाहूं तहसील को जोड़ने वाली यह सड़क ग्रामीणों के लिए प्रमुख मार्ग है, लेकिन नदी पार करते समय लोगों को भारी असुविधा झेलनी पड़ती है। ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से चंदा एकत्र कर बसुई नदी पर पिलर निर्माण कराया है। उनका कहना है कि मानक के अनुसार पिलर मजबूत एवं सही बनाए गए हैं, परंतु अब छत डालने के लिए उनके पास धन नहीं है। नदी के दोनों ओर लगभग एक किलोमीटर सड़क कच्ची है–नदी से कुंदनपुर की ओर लगभग 200 मीटर और धनापुर-बरसठी की ओर लगभग 800 मीटर–जबकि शेष सड़क पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई है। ग्रामीणों का कहना है कि मिनी पुल के निर्माण से बरसठी, जरौटा, धनापुर, कुंदनपुर, उमरम, कन्हवंशीपुर, धर्मदासपुर समेत कई गांवों के लोगों, छात्रों और किसानों को आवागमन में राहत मिलेगी। उनका आग्रह है कि जिलाधिकारी जौनपुर और जल संसाधन विकास मंत्रालय इस मामले को संज्ञान में लेकर शीघ्र पुल निर्माण कार्य आरंभ करें या मौजूदा पिलरों पर छत डलवाने की व्यवस्था करें। जज सिंह अन्ना ने बताया कि जब तक प्रशासन कार्रवाई नहीं करता, तब तक यह धरना और प्रदर्शन जारी रहेगा। ग्रामीणों की यह मांग अब जनआंदोलन का रूप ले चुकी है।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विचार मंच की आमसभा आज

मुंबई। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विचार मंच की ओर से 22 नवंबर, शनिवार को अपराह्न 3.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक नवी मुंबई के सानपाड़ा (पश्चिम) में वर्ना मिल्क डेयरी के पास स्थित द. कॉपोरेट पार्क, प्रथम तल पर आमसभा आयोजित की गई है। इस आमसभा को संस्था के भविष्य की रूपरेखा तय करने वाली महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है,जिसमें कई नीतिगत और संगठनात्मक विषयों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में मंच के संयोजक आर.एन. यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में कोर कमेटी के गठन, पदाधिकारियों के चयन, संस्था के झंडे के रंग का निर्धारण, सलाहकार टीम का गठन तथा महासचिव के नाम के अनुमोदन जैसे ज्वलंत मुद्दों पर व्यापक विचार-विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत और संगठित दिशा देने के लिए यह बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दौरान वरिष्ठ साहित्यकार व पत्रकार मधुराज 'मधु' विशेष रूप से उपस्थित रहकर सभी सदस्यों का मार्गदर्शन करेंगे। मंच के नियमों के अनुसार, कोर कमेटी में वही सदस्य चयनित होंगे जो इस मौके पर उपस्थित रहेंगे, अन्यथा अनुपस्थित सदस्यों के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा।

सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 25 नवंबर से शुरू होगा मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का अभियान

सिवान (उत्तरशक्ति)। महाराजगंज बिहार के सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में आगामी चुनावों की तैयारी तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियों की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। आयोग के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 30 सितंबर 2025 से 6 नवंबर 2025 तक शिक्षक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन लिया गया था। इस अवधि में बड़ी संख्या में शिक्षकों ने अपने संबंधित प्रखंड कार्यालयों में फॉर्म जमा कर दिया था, लेकिन कई शिक्षक चुनावी कार्य, सरकारी जिम्मेदारियों, अवकाश या अन्य व्यक्तिगत कारणों से आवेदन नहीं कर सके। ऐसे शिक्षकों तथा उन अभ्यर्थियों के लिए, जिनका नाम 25 नवंबर 2025 को प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची में प्रदर्शित नहीं हो पाया है, दावा-आपत्ति की प्रक्रिया 25 नवंबर से शुरू होकर 10 दिसंबर 2025 तक चलेगी। इस अवधि में कोई भी पात्र शिक्षक फॉर्म-19 भरकर दावा या आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसके तहत दो श्रेणियों के लिए अवसर उपलब्ध है- पहली, जिन शिक्षकों ने पूर्व निर्धारित समय में आवेदन किया था, लेकिन नाम सूची में शामिल नहीं हुआ है, और दूसरी, जो शिक्षक आवेदन करने से वंचित रह गए थे। निर्वाचन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि सभी शिक्षक 25 नवंबर को जारी होने वाली संशोधित मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांचें। यदि सूची में नाम नहीं मिलता है, तो निर्धारित प्रपत्र फॉर्म-19 भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबद्ध प्रखंड कार्यालय में जमा करें। अधिकारी 10 दिसंबर तक दायर किए गए सभी दावों और आपत्तियों की जांच करेंगे और सत्यापन के बाद नाम शामिल करने पर निर्णय लिया जाएगा। प्रशासन ने शिक्षकों से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया को गंभीरता से लें और अंतिम तिथि से पहले आवेदन सुनिश्चित करें, ताकि आगामी शिक्षक निर्वाचन में उनका मताधिकार प्रभावित न हो।

वसई-विरार में नई राउंड बस सर्विस का शुभारंभ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा और सुगम

वसई रोड। वसई-विरार सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ट्रांसपोर्ट विभाग ने शहर की सार्वजनिक परिवहन सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वसई रेलवे स्टेशन (ईस्ट) से एवरशाइन सिटी के बीच नई राउंड बस सर्विस की शुरूआत की है। इस नई सर्विस का उद्घाटन वसई की विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने एवर की ।

स्नेहा दुबे पंडित की अध्यक्षता में बैठक संपन्न

वसई रोड। वसई वेस्ट स्थित एम एल ए पब्लिक रिलेशन ऑफिस में आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिसकी अध्यक्षता वसई की विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य वसई विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्राम पंचायतों रणगांव, कलंब, खोचिवड़े, अनार्ला, अनार्ला किला, टेंभी कोल्हापुर और वसलाई में महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, जल जीवन मिशन तथा वसई-विरार सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा चल रहे जलापूर्ति कार्यों की समीक्षा करना था।

बैठक में जल सप्लाई प्रोजेक्ट्स की प्रगति और चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। दो दिनों के भीतर पेंडिंग कार्यों की विस्तृत सूची जमा की जाएगी। कार्य में लापरवाही बरतने वाले ग्राम सेवकों को नोटिस जारी किए जाएंगे।

सरकारी भूमि पर पानी की टंकी के निर्माण में बाधा डालने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी अधूरे जलापूर्ति कार्यों को अगले 125 दिनों में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने कहा कि उद्देश्य यह है कि हर ग्राम पंचायत में जलापूर्ति कार्य तेजी और गुणवत्ता के साथ पूरे हों, ताकि नागरिकों को निरंतर एवं सुविधाजनक पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। बैठक में जल आपूर्ति विभाग के विभिन्न अधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख थे।

उप अभियंता सुरेंद्र ठाकरे, अधिशासी अभियंता एलए बोर्डे, उप अभियंता जेडी जाधव, अधिशासी अभियंता आरसी पाटिल, उप अभियंता प्रज्वल नरेंद्र भोईर, कनिष्ठ अभियंती पीपी ताजाने, मोनाली पाटिल, वरुण संग्राम राउत, कलंब की सरपंच अमिता कपिल म्हात्रे, अनार्ला किल्ला सरपंच पूजा सलिल मेहर-म्हात्रे, और अन्य स्थानीय पदाधिकारी। बैठक के अंत में सभी अधिकारियों ने निर्धारित समय में काम पूर्ण करने और वसई के नागरिकों को निर्बाध जलापूर्ति उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

वसईझ्रविरार में गड्ढों की मरम्मत पर 68 करोड़ खर्च के बावजूद सड़कों की हालत खराब मनोज बारोट ने की कार्रवाई की मांग

नालासोपारा। वसईझ्रविरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा गड्ढों की मरम्मत और सड़क सुधार कार्यों के लिए 68 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट जारी किए जाने के बावजूद शहर की अधिकांश सड़कों पर मरम्मत कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसके चलते लाखों नागरिकों को मानसून के महीनों के बाद भी बदहाल सड़कों और खतरनाक गड्ढों से होकर गुजरना पड़ रहा है। इस गंभीर स्थिति पर ध्यान आकर्षित करते हुए भाजपा वसई जिला के जनरल सेक्रेटरी मनोज बारोट ने संबंधित अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपये का वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद भी सड़क मरम्मत कार्य न होना, प्रशासन की उदासीनता और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। छठ पूजा से पहले 25 अक्टूबर को हुई ऑल पार्टी मीटिंग में म्युनिसिपल कमिश्नर मनोज कुमार सूर्यवंशी ने आश्वासन दिया था कि 30 नवंबर तक पूरा वसईझ्रविरार गड्ढा-मुक्त कर दिया जाएगा।

इसके बाद सड़क सुधार और गड्ढा मरम्मत के लिए टेंडर मंगाए गए और 68 करोड़ रुपये का फंड मंजूर करके कॉन्ट्रैक्टर को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया। लेकिन आज तक शहर में कई जगह रोड रिपेयर कार्य शुरू ही नहीं हुआ है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है और नागरिकों में नाराजगी है।

सड़क मरम्मत में देरी पर तंज कसते हुए मनोज बारोट ने कहा कि अगर नगर निगम और कॉन्ट्रैक्टर सड़कें रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम फुटपाथ को ही साफ कर दें ताकि लोग सुरक्षित चल सकें। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और इंचार्ज म्युनिसिपल कमिश्नर इंदुरानी जाखड़ को पत्र लिखकर शिकायत की है और तुरंत कार्रवाई की मांग की है। बारोट ने आरोप लगाया कि वीवीएमसी अधिकारियों की लापरवाही और आंतरिक स्वार्थों के कारण ऐसे कॉन्ट्रैक्टर चुने जाते हैं जो समय पर या निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार काम नहीं करते।

वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद भी कार्य में तेजी नहीं दिखती, जिससे नागरिकों को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल पाता और स्थिति जस की तस बनी रहती है। उन्होंने मांग की है कि काम में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्टरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही न हो।

रांची में टीबी मरीजों के लिए आरके एचआईवी एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर और एसबीआई फाउंडेशन द्वारा न्यूट्रिशन किट का वितरण

रांची। आरके एचआईवी एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर के चेयरमैन डॉ. धर्मेंद्र कुमार के नेतृत्व में रांची में टीबी पेशेंट्स के लिए न्यूट्रिशन किट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम का सफल आयोजन किया गया और टीबी मोबाइल मेडिकल यूनिट का लॉन्च भी हुआ. यह पहल एसबीआई फाउंडेशन ने सीएसआर प्रोग्राम एसबीआईएफ जीवनम के अंतर्गत आर के एच आई वी एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर, मुंबई के साथ मिलकर की. एसबीआई फाउंडेशन के एमडी और सीईओ संजय प्रकाश और डॉ. धर्मेंद्र कुमार की शानदार लीडरशिप में आयोजित इस इवेंट में मौजूद जाने-माने लोगों से 300 से ज्यादा ळइ मरीजों को न्यूट्रिशन किट मिली. कार्यक्रम में जाने-माने लोगों ने प्रेरणादायक भाषण दिए. उसके बाद न्यूट्रिशन किट का वितरण किया गया. फिर टीबी मोबाइल मेडिकल यूनिट का ग्रैंड फ्लैग-ऑफ हुआ। इस इवेंट में ये जाने-माने मेहमान संजय प्रकाश (एमडी और सीईओ, एसबीआई फाउंडेशन (चीफ गेस्ट), शशि प्रकाश झा (मिशन डायरेक्टर, ठफ्लट), डॉ. कमलेश कुमार (स्टेट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर, झारखंड), राजाराम चव्हाण (सीनियर मैनेजर झ हेल्थ और महिला एम्पावरमेंट, एसबीआई फाउंडेशन), डॉ. एस. बास्की (डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर, रांची), प्रवीण कुमार सिंह (डीपीएम, रांची), निकिता आरोहन (असिस्टेंट मैनेजर – महिला एम्पावरमेंट, एसबीआई फाउंडेशन) सम्मिलित हुए।

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आर.के. एचआईवी एड्स रिसर्च ऐंड केयर सेंटर एवं डॉक्टर 365 के अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र कुमार द्वारा देश भर मे कई मेगा मेडिकल शिविर का आयोजन किया जाता रहा है जिससे लाखों मरीजों ने लाभ उठाया है. व्हीलचेयर, न्यूट्रीशन किट और चश्मे वितरित किए जाते हैं. आर के एचआईवी एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर सबसे बड़े और सबसे अधिक मुफ्त जनरल मेडिकल कैंप के आयोजन के लिए मशहूर है. संस्था के द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में बरसों से लगातार मुफ्त मेडिकल कैम्प किए जा रहे हैं जिसमें लाखों लोग लाभ लेते हैं. फ्री हेल्थ चेकअप, फ्री आँखों की जांच, मुफ्त सभी प्रकार की दवाइयां और मुफ्त चश्मे का वितरण किया जाता है. मेडिकल कैंप मे सैकड़ों डॉक्टर्स अपना योगदान देते हैं. टीबी के मरीजों को न्यूट्रिशन किट दिया जाता है. डॉ धर्मेंद्र कुमार देश को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं।

महाराजगंज ग्रामीण में आंगनबाड़ी केंद्र समय पर खुलना अनिवार्य: सीडीपीओ

सिवान (उत्तरशक्ति)। बिहार के सिवान जिला अंतर्गत महाराजगंज प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन को लेकर विभाग अब पूरी तरह सख्त हो गया है।सभी केंद्रों को प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर एक बजे तक अनिवार्य रूप से खोलने का निर्देश दिया गया है। समय पर संचालन नहीं होने की शिकायतों के बाद बाल विकास परियोजना कार्यालय ने विशेष निगरानी शुरू कर दी है। सीडीपीओ कलावती ने कहा कि किसी भी सूरत में आंगनबाड़ी केंद्र बंद पाए जाने पर संबंधित सेविका-सहायिका पर चयनमुक्ति की प्रक्रिया लागू की जाएगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं का सही लाभ तभी संभव है, जब केंद्र समय पर खुलें और सेवाएं नियमित रूप से दी जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि केंद्रों पर मौजूद बच्चे, सेविका और सहायिका ड्रेस कोड में रहें, जिससे अनुशासन और पहचान दोनों सुनिश्चित हो सके।

नई एनर्जी, देशभक्ति और फिटनेस के लिए प्रेरणा: इंडियनऑयल डब्ल्यूएनसी नेवी हाफ मैराथन का आयोजन

मुंबई। इंडियनऑयल डब्ल्यूएनसी नेवी हाफ मैराथन मुंबई के सबसे जाने-माने स्पोर्ट्स इवेंट्स में से एक बन गया है, जो धीरज की भावना और देश के गर्व का जश्न है। नेवी डे सेलिब्रेशन के हिस्से के तौर पर वेस्टर्न नेवल कमांड द्वारा आयोजित यह इवेंट, आम लोगों को भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा करने वाले सफेद वर्दी वाले पुरुषों और महिलाओं के साथ दौड़ने का एक खास मौका देता है। इंडियनऑयल डब्ल्यूएनसी नेवी हाफ मैराथन की तारीख-रविवार, 23 नवंबर 2025, पता-क्रॉस मैदान,(आजाद मैदान/बॉम्बे जिमखाना के सामने) है। 2025 एडिशन को वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, एफओसी-इन-सी, वेस्टर्न नेवल कमांड, और श्री अरविंदर सिंह साहनी, चेयरमैन, इंडियनऑयल हरी झंडी दिखाएंगे। उनकी मिली-जुली मौजूदगी भारत की समुद्री सुरक्षा और देश के एनर्जी सेक्टर के बीच मजबूत पार्टनरशिप को दिखाती है।

2016 में पहले डब्ल्यूएनसी नेवी हाफ मैराथन में 4,560 लोगों ने हिस्सा लिया था। 2018 में इंडियनऑयल के टाइटल स्पॉन्सर बनने के बाद यह इवेंट और बड़ा हो गया। तब से, हर साल कुल रजिस्ट्रेशन तेजी से बढ़ रहे हैं। इस साल, 20,000 से ज्यादा रनर्स के हिस्सा लेने की उम्मीद है। इस पार्टनरशिप ने इवेंट का लेवल बढ़ाया है और रनर्स के अनुभव को बेहतर बनाया है, जिससे मैराथन को वर्ल्ड ऐथैलेटिक्स रोड रेस का लेबल मिला है।

इस मैराथन की सबसे आकर्षक बात इसका शानदार रूट है, जिसे रनर्स ने देश के सबसे सुंदर रूट्स में से एक कहा है। रेस ऐतिहासिक बैलार्ड एस्टेट से शुरू होती है, जो रनर्स को पुरानी मुंबई के आकर्षक कॉलोनियल माहौल से गुजारती है। जैसे ही पार्टिसिपेंट्स सीएसएमटी और ओवल मैदान रूट पर आगे बढ़ते हैं, उन्हें शानदार हाई कोर्ट और राजाबाई टॉवर दिखाई देते हैं। रूट का सबसे आकर्षक हिस्सा मरीन ड्राइव का किनारा है।

जैसे ही रनर्स क्वींस नेकलेस तक पहुँचते हैं, वे एक तरफ विशाल अरब सागर और दूसरी तरफ मुंबई की मशहूर आर्ट डेको स्काईलाइन देख सकते हैं। 21 किमी के रनर्स के लिए, यह रूट वर्ली सी फेस तक जाता है, जो एक फ्लैट, तेज और हवादार कोर्स देता है जो पर्सनल बेस्ट पाने के लिए एकदम सही है। इंडियनऑयल, जिसे भारत की एनर्जी के नाम से जाना जाता है और जो एक महारत्न कंपनी के तौर पर देश के डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभा रही है, देश के हर कोने में मौजूद है। डब्ल्यूएनसी नेवी हाफ मैराथन जैसे इवेंट्स को प्रमोट कर-के, इंडियनऑयल एक हेल्दी, फिट और ज्यादा एक्टिव भारत की ओर काम कर रहा है।

NECT का प्रतापगढ़ ग्रामीण क्षेत्र में नि:शुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर सम्पन्न

प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के मदुरा रानीगंज गाँव में नवी मुंबई चैरिटेबल ट्रस्ट (NECT) द्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य एवं नेत्र शिविर ने क्षेत्र में नई उम्मीद जगाई। ट्रस्ट के 15वें स्थापना दिवस और संस्थापक ट्रस्टी रमेश नारायण त्रिपाठी के जन्मदिन पर समर्पित इस आयोजन में सुबह से ही ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। तपती धूप के बावजूद लोगों में उत्साह था और स्वास्थ्य सेवाएँ पाने की खुशी उनके चेहरों पर झलक रही थी। डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम ने नेत्र जाँच, सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण, दवा वितरण और परामर्श अत्यंत व्यवस्थित ढंग से किया। कई मरीजों के पुराने नेत्र व स्वास्थ्य रोगों के उपचार की ज़िम्मेदारी आगे भी ट्रस्ट ने लेने का आश्वासन दिया। बच्चों को स्कूल बैग, पेन, पेंसिल और पानी की बोतलें वितरित की गईं, जिससे उनमें विशेष उत्साह देखा गया। मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री मोती सिंह ने कहा कि सेवा ही सच्ची राष्ट्रभक्ति है और यह शिविर ग्रामीण जीवन में सकारात्मक बदलाव का मार्ग प्रशस्त करेगा। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहे–पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रो. शिवाकांत ओझा, विधायक राजेंद्र मौर्य, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा ओम प्रकाश त्रिपाठी, भाजपा नेता शिवप्रकाश मिश्र सेनानी, विनोद पाण्डेय, पूनम इंसान, डॉ. नीरज त्रिपाठी, महेन्द्र शुक्ला, डी.एन. मिश्रा, उद्योगपति पंकज मिश्रा, प्रो. वी.के. त्रिपाठी, प्रो. आर.के. त्रिपाठी, शशिकांत दास, देवेंद्र पाठक महाराज, मधुकर महाराज, मोहन जयरामानी, समाजसेवी अरुण मिश्रा, पत्रकार अविनाश पाण्डेय, समाजसेवी राजेश पाण्डेय, रमाकांत दूबे, अनिल बारी तथा संचालनकर्ता विमल चन्द्र दीप। ग्रामीणों ने आयोजन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि गाँव में इतना बड़ा और सार्थक कार्यक्रम पहले कभी नहीं हुआ। ठएउळ ने भविष्य में महिला स्वास्थ्य शिविर, छात्रवृत्ति और बुजुर्गों के हेल्थ कार्ड जैसी योजनाएँ शुरू करने की घोषणा की। यह शिविर ग्रामीण विकास के एक नए अध्याय की शुरूआत साबित हुआ।

भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है मां जरती का मंदिर

सिवान (उत्तरशक्ति)। बिहार के सिवान जिला अंतर्गत महाराजगंज नगर पंचायत के इंदौली गांव स्थित गण्डकी नहर किनारे माता जरती की मंदिर हैं। मंदिर के पुजारी आचार्य सुरेंद्र तिवारी ने बताया कि मंदिर पुराना है। यहाँ से सौ मीटर पर दक्षिण साइड में एक गंडकी नहर भी हैं। नगर के उत्तर जरती माई का प्रसिद्ध मंदिर है और लोगो का एक आस्था का केंद्र बन गया हैं। उक्त मंदिर का इतिहास पुराना है।, आज भी लोग दूर दराज से लोग यहां पहुंचते हैं। कुछ वर्ष पूर्व झाड़ी में माता का एक पिंड था। आज के समय बहुत से अनोखे तरीके से निर्माण कर मंदिर का रूप दिया गया, जो आकर्षण का भी केंद्र है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह जगह झपसी सिंदुआर द्वारा कौड़ी कमख्या से लाई गई पिंडी स्थापित नाम से जाना जाता था। डेढ़ दशक पूर्व महाराजगंज पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार के मन में माता के मंदिर बनाने की इच्छा जागी । भव्य मंदिर भी बना। उक्त मंदिर परिसर में सोमवार व शुक्रवार को श्रद्धालु पूजा करने आते है। दशहरे की समय यहां भारी भीड़ जुटती है। लोक आस्था भी है लोगों की मान्यता है कि इन देवी देवताओं के दरबार से कोई खाली हाथ वापस नहीं लौटता है।